



TIMES OF INDIA

NEW DELHI Page 12 Price Rs. 3.00

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इंसाफ़ की डगर पर

WEEKLY HINDI, ENGLISH, URDU

www.timesofindia.com

WED 18 FEB - TUE 24 FEB 2026

VOL. 14. ISSUE 08

RNI No. DELMUL/2012/47011

दिल्ली दंगे: लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट का अहम फैसला

नई दिल्ली: सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी और पूरी दिल्ली में दहशत फैल गई थी। इसके 6 साल बाद भी, दंगों से जुड़े 53 क्रिमिनल केस में सिर्फ एक व्यक्ति को गैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया गया है।

2025 तक, गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होना, हथियारों के साथ दंगा करना, विस्फोटक पदार्थों का इस्तेमाल, चोरी और लोगों को गुमराह करने वाले बयान के आधार पर दर्ज 53 क्रिमिनल केस में से सिर्फ 11 में ही सजा हुई है।

TOI के 53 केस के एनालिसिस से पता चला है कि अब तक 40 से ज्यादा लोगों को दोषी ठहराया जा चुका है, जबकि 100 से ज्यादा को बरी कर दिया गया और 75 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। दंगों के सिलसिले में कुल 758 केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें 53 क्रिमिनल केस शामिल हैं। इस दौरान, जज बदलते रहे हैं, और जांच और सबूतों पर कड़ी टिप्पणियां की हैं।

कड़कड़डूमा कॉम्प्लेक्स में अकेले



नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दंगों से जुड़े मुख्य केस चल रहे थे, जिसमें कई जजों ने मामलों की सुनवाई की, जिनमें विनोद यादव, वीरेंद्र भट्ट, पुलस्त्य प्रमाचला और मौजूदा परवीन सिंह ने नाम शामिल हैं। उसी कॉम्प्लेक्स में एक और स्पेशल कोर्ट हाई-प्रोफाइल केस देखरेख कर रहा है, जिसमें स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद, शरजील इमाम, AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर आरोप

लगाए गए हैं। उन पर एंटी-टेरर कानून UAPA के तहत आरोप लगाए गए हैं। यहां भी जजों के बार-बार ट्रांसफर का मतलब था कि दलीलें दोहरानी पड़ीं और रिकॉर्ड फिर से देखने पड़े, जिससे केस शुरू होने में देरी हुई।

पिछले कुछ सालों में, स्पेशल कोर्ट उन जांचों की आलोचना करते रहे हैं जिनमें बरी होने के फैसले रिकॉर्ड किए गए हैं। जजों ने कई बार बताया है कि प्रॉसिक्यूशन ने नकली गवाह

पेश किए या ऐसे सबूतों पर भरोसा किया जो 'गढ़े हुए' लग रहे थे।

उदाहरण के लिए, करावल नगर से जुड़े एक ट्रायल में, कोर्ट ने अप्रैल 2025 में सलमान की कथित हत्या के आरोपियों को बरी कर दिया और जिस तरह से केस तैयार किया गया था, उसके बारे में साफ टिप्पणी की। कोर्ट ने दर्ज किया था, 'यह कहना काफी है कि इस मामले में सलमान की गैर-इरादतन हत्या के लिए सभी आरोपियों

पर मुकदमा चलाना, कानून की सही समझ पर आधारित नहीं था।' इसमें यह भी कहा गया कि जांच अधिकारी ने चार्जशीट में जो नतीजा निकाला, उससे पता चलता है कि असली अपराधियों का पता नहीं लगाया जा सका।

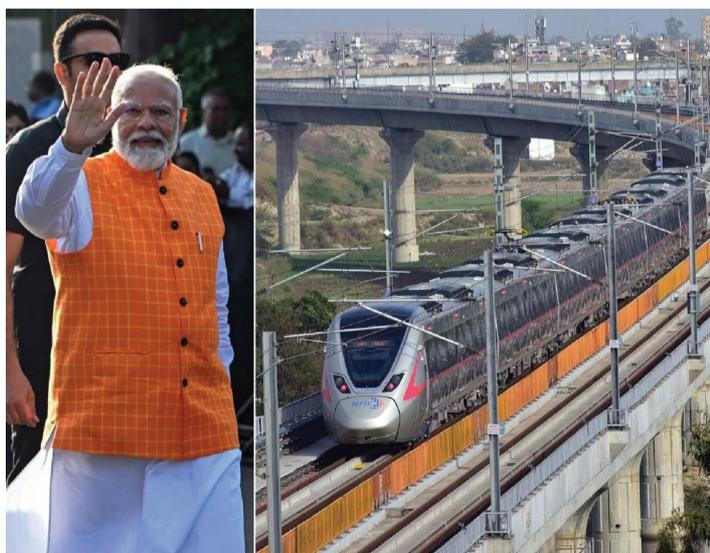
कोर्ट ने कहा कि अगर दिल्ली पुलिस दोषियों की पहचान नहीं कर पा रही थी, तो उसे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न करते हुए 'अनट्रेस्टेड रिपोर्ट' फाइल करनी चाहिए थी। एक और बरी करने के फैसले में, जज पुलस्त्य प्रमाचला ने हाशिम अली की हत्या के 12 आरोपियों को बरी कर दिया, यह देखते हुए कि हालात के सबूतों के नाम पर, अभियोजन पक्ष सबूत के सिर्फ टुकड़े ही दिखा सका।

कोर्ट ने 'कट्टर हिंदू एकता' नाम के ग्रुप के वॉट्सएप चैट पर भरोसा करने से मना कर दिया, यह देखते हुए कि पुलिस ने - दूसरी हत्याओं से जुड़े मामलों में भी उन्हीं चैट का जिक्र किया था। दंगों और दूसरे अपराधों से जुड़े कई मामलों की आलोचना हुई है, जिन्हें कोर्ट ने घटिया या मजाकिया जांच बताया है।

नमो भारत कॉरिडोर ने बनाया नया कीर्तिमान, एक दिन में 1 लाख से अधिक यात्रियों ने किया सफर

नई दिल्ली। नमो भारत कॉरिडोर और मेरठ मेट्रो के पूरे खंड के संचालन शुरू होने के बाद यात्रियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। 23 फरवरी को कॉरिडोर ने नया रिकॉर्ड कायम करते हुए एक ही दिन में 1 लाख से अधिक यात्रियों की आवाजाही दर्ज की। यह अब तक की सर्वाधिक दैनिक राइडरशिप है और पहले के औसत लगभग 60 हजार यात्रियों की तुलना में करीब 70 प्रतिशत अधिक है। सोमवार होने के कारण कार्यदिवस की भीड़ का असर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया और ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों, छात्र-छात्राओं तथा दैनिक यात्रियों ने बड़ी संख्या में इस सेवा का उपयोग किया।

मेरठ के केंद्रीय क्षेत्र में स्थित बेगमपुल स्टेशन सबसे व्यस्त रहा।



सेंट्रल मार्केट और बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के बीच स्थित यह स्टेशन नमो भारत और मेरठ मेट्रो दोनों सेवाएं प्रदान

करता है, जिसके कारण यहां यात्रियों की सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई। आनंद विहार स्टेशन ने दूसरी सबसे

अधिक राइडरशिप दर्ज की। यह स्टेशन रेलवे, दिल्ली मेट्रो की विभिन्न लाइनों, आईएसबीटी और बस सेवाओं से जुड़ा होने के कारण प्रमुख ट्रांजिट हब बन चुका है। गाजियाबाद स्टेशन पर भी यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई, जिससे स्पष्ट है कि कॉरिडोर क्षेत्रीय आवागमन का अहम साधन बनता जा रहा है।

प्रधानमंत्री द्वारा नए खंडों के उद्घाटन के बाद सराय काले खां से मोदीपुरम तक पूरी सेवा शुरू हो गई है। सराय काले खां, शताब्दी नगर और मोदीपुरम जैसे नए स्टेशनों पर भी अच्छी राइडरशिप दर्ज की गई, जबकि पहले से संचालित न्यू अशोक नगर स्टेशन पर भी यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। यात्रियों

का उत्साह इस बात से भी झलकता है कि कई परिवार और युवा समूह इस नई सेवा का अनुभव लेने पहुंचे और यात्रा के दौरान फोटो व वीडियो साझा करते नजर आए। सोशल मीडिया पर नमो भारत की रीलस और सेल्फी की भरमार रही।

विशेषज्ञों का मानना है कि हाई-स्पीड, आरामदायक और समयबद्ध सेवा के कारण नमो भारत कॉरिडोर तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाओं के चलते यह परियोजना क्षेत्रीय परिवहन व्यवस्था को नई दिशा दे रही है। एक दिन में 1 लाख से अधिक यात्रियों का आंकड़ा पार करना इस कॉरिडोर की बढ़ती स्वीकार्यता और जनता के भरोसे का प्रतीक माना जा रहा है।

हिन्दू राजाओं द्वारा मंदिर तोड़ने का इतिहास , एक सच



Ali Aadil Khan
Editor

कलाप्रिया मंदिर को नष्ट कर दिया.

असल में मंदिरों को लूटने की एक वजह यह थी कि यहाँ बहुत धन इकट्ठा होता था , आज भी अगर देखें तो केरल के श्री पद्मणेश्वर मंदिर से 1 ,20000 , करोड़ की धन-संपत्ति मिली थी .भारत के मंदिरों में संपत्ति का जमा होना पुराण इतिहास और भारत पर आक्रमण होने का एक कारण

अँगरेज़ सम्रज्वादी शासन के लिए यह घाटे का सौदा था लिहाज़ा इस शांतिपूर्ण माहौल में अंग्रेजों ने विघ्न डाला और उन्हें एक-दूसरे से लड़वाना शुरू कर दिया.' इसके लिए Divide and Rule का फार्मूला सबसे ज़्यादा रास आया . आज अंग्रेजों की उसी नीति को देश में follow किया जा रहा है ,जो एक जमात को रास आ गयी है

संस्थाओं को किस बात की जलन है ? देश में झूठे और फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर अखंड भारत को खंडित करने वालों की योजना देश को बर्बाद करने की नज़र आती है . जो हुकूमतें मोहब्बतों यानि लव के खिलाफ , हया और लज्जा यानि परदे के खिलाफ , अज्ञान , भजन कीर्तन के खिलाफ कानून बनाती हो ऐसे योजना

क्या देश की वर्तमान राजनीति फिर किसी महामारी को निमंत्रण की खोज में है ? अभी तैरती लाशों का मंज़र नज़र से पूरी तरह ओझल भी नहीं हुआ है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद जैसे गड़े मुर्दे उखाड़ने की पुनरावृत्ति शुरू हो गयी है . वैसे किसी ने बड़ा सही कहा था कि जो काम आपदाओं के चलते किये जा सकते हैं वो नार्मल

केरल के श्री पद्मणेश्वर मंदिर से 1 ,20000 , करोड़ की धन-संपत्ति मिली ज्ञानव्यापी मस्जिद के बारे में औरंगज़ेब के काल की तारिख को जानने से पहले यह भी समझना ज़रूरी है कि कश्मीर के 11 वीं सदी के शासक राजा हर्षदेव सहित अनेक हिन्दू राजाओं ने संपत्ति के लिए मंदिरों को लूटा और कई को नष्ट भी किया. मराठा सेनाओं ने टीपू सुल्तान को नीचा दिखाने के लिए मैसूर के श्रीरंगपट्टनम मंदिर को ध्वस्त कर दिया था

इसके अलावा सन 642 में पल्लव राजा नरसिंहवर्मन ने चालुक्यों की राजधानी वातापी में गणेश के मंदिर को लूटा और उसके बाद उसे ध्वस्त कर दिया . आठवीं सदी में बंगाली सैनिकों ने विष्णु मंदिर को तोड़ा.

9 वीं सदी में पांड्य राजा सरीमारा सरीवल्लभ ने लंका पर आक्रमण कर जो भारत का ही हिस्सा था वहां सभी मंदिरों को नष्ट कर दिया. 11 वीं सदी में चोल राजा ने अपने पड़ोसी चालुक्य, कालिंग, और पाल राजाओं से क्रीमती मूर्तियां को छीन कर अपने राजधानी मे लाकर रख लीं .

11 वीं सदी के मध्य में राजाधिराज ने चालुक्य को हराया और शाही मंदिरों को लूट कर उनका विनाश कर दिया. 10 वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय ने जमुना नदी के पास कल्पा में



BABRI MASJID

GYANVAPI MOSQUE

ये संपत्ति रहा है न की किसी एक धर्म का विरोध और किसी दुसरे धर्म का प्रचार इत्यादि .

एक बड़ी सच्चाई को सामने रखते हुए 'हिन्दू स्वराज ' नामी पु:तक में महात्मा गांधी लिखते हैं "मुस्लिम राजाओं के शासनकाल में हिन्दू समाज फला फूला जबकि हिन्दू राजाओं के राज में मुसलमान. दोनों ही पक्षों को यह अच्छे से पता था कि आपस में लड़ना आत्मघाती होगा और यह भी कि दोनों में से किसी को भी हथियारों के दम पर अपने धर्म का त्याग करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता.

लेकिन दोनों समुदायों का आपसी सामंजस्य और सोहार्द व् सांप्रदायिक सद्भाव

लेकिन देश लगातार कमज़ोर होता जा रहा है ,और दुश्मन को इसका पूरा लाभ मिल रहा है . ताज महल भले विवादों में चल रहा हो किन्तु पुरातत्व विभाग के इस धरोहर से भारत को हर साल लगभग 50 से 55 करोड़ की आमदनी होती है . 2018 -19 में यह आमदनी बढ़कर 75 करोड़ पहुँच गयी . इसके अलावा मशहूर ट्रेवल ऑनलाइन कंपनी ट्रिप एडवाइज़र ने 2018 ट्रेवलर्स च्वाइस अवॉर्ड में ताज महल को दुनिया का छठवां और एशिया के दूसरे लैंडमार्क से नवाज़ा है.

देश को Tourism से होने वाली आमदनी और दुनिया में भारत के धरोहर की शोहरत से आखिर इन

कर्मियों की नीयत से साफ़ ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है और फिर देश के भविष्य को अंधेरों से कोई नहीं बचा सकता .

देश की कुछ संस्थाएं अमन , शांति और विकास की जगह नफ़रत , द्वेष और विनाश का माहौल बनाये रखना चाहती हैं , अवासी मुद्दों से भटका कर , सांप्रदायिक और धार्मिक मुद्दों में जनता को उलझाए रखना उनकी योजना का हिस्सा है , जिसको सियासी संरक्षण प्राप्त है . ऐसी संस्थाएं और सोच देश के दुश्मनों के एजेंट के सिवा और कुछ नहीं हो सकती जो लगातार धार्मिक और जातीय नफ़रत के ज़रिये उन्माद को ज़िंदा रखने में व्यस्त है .

हालात में करने मुमकिन नहीं हैं , अब जिस प्रकार देश में राम मंदिर की आंधी के बाद ज्ञानव्यापी मस्जिद के मुद्दे पर देश की मीडिया को लगा कर एक बड़ी आपदा या मुद्दा बना दिया गया है और इसी दौरान चुपके से चीन की कंपनी को 38000 रेल के पहिये बनाने का कारोबार दे दिया गया है .यानी दुश्मन देश के साथ कारोबारी संधियां की जा रही हैं. और आपदा में अवसर तलाश लिया गया है .अगर समय रहते देश की जनता नहीं उजागर हुई तो हालात बाद से बदतर होते चले जाएंगे और देश विनाश की ओर बढ़ता जाएगा जिसके बाद सुरक्षित और सुकून से कोई नहीं होगा .

चौथी बरसी पर कीव में समर्थन, ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान

रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष अब अपने पांचवे साल में प्रवेश कर रहा है। इसके बाद भी इस संघर्ष के खत्म होने की संभावनाएं कम दिख रही हैं। इसका बड़ा कारण शांति समझौते पर दोनों देशों का अलग-अलग और सख्त रुख है। इसी बीच इस संघर्ष की चौथी बरसी पर यूरोपीय नेता कीव के दौरे पर पहुंचे। आइए जानते हैं इस दौरान ज़ेलेंस्की ने क्या कहा?

रूस और यूक्रेन के बीच जारी भयावह संघर्ष की चौथी बरसी पर मंगलवार को यूरोप के एक दर्जन से ज्यादा वरिष्ठ नेता यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। उनका यह दौरा यूक्रेन के प्रति समर्थन दिखाने के लिए था। यह युद्ध चार साल पहले शुरू हुआ था और अब तक इसमें दसियों हजार लोगों की जान जा चुकी है। इस संघर्ष ने पूरे यूरोप को चिंता में डाल रखा है कि रूस की मंशा आखिर कितनी बड़ी है। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनका देश रूस की बड़ी और बेहतर हथियारों से लैस सेना का डटकर सामना कर रहा है।

उन्होंने बताया कि पिछले एक



साल में रूस ने यूक्रेन के केवल 0.79 प्रतिशत इलाके पर ही कब्जा किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमने अपनी आजादी की रक्षा की है, हमने अपना देश नहीं खोया है। उन्होंने यह भी कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने मकसद में सफल नहीं हुए हैं और न ही वे यूक्रेनियों का हौसला तोड़ पाए हैं। हालांकि युद्ध अब पांचवें साल में प्रवेश कर रहा है और हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। अमेरिका की पहल पर शांति वार्ता की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समझौता नहीं हो सका है। सबसे बड़ी अड़चन पूर्वी यूक्रेन

के डोनबास क्षेत्र को लेकर है। यह इलाका उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है और इसका बड़ा हिस्सा अभी रूसी कब्जे में है। यूक्रेन चाहता है कि युद्ध के बाद उसकी सुरक्षा की पक्की गारंटी हो, ताकि भविष्य में रूस फिर हमला न कर सके।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों पक्षों के मारे गए, घायल या लापता सैनिकों की संख्या वसंत तक 20 लाख तक पहुंच सकती है। यह संख्या दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी बड़े देश के लिए सबसे ज्यादा हो सकती है। इस अनुमान को सामरिक और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र ने जारी किया है। इस संघर्ष को लेकर यूरोपीय नेताओं

को डर है कि अगर रूस को नहीं रोका गया तो उसका असर पूरे महाद्वीप की सुरक्षा पर पड़ेगा। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि पिछले चार साल यूक्रेन और पूरे यूरोप के लिए एक बुरे सपने जैसे रहे हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध फिर से यूरोप में लौट आया है और इसे खत्म करने के लिए हमें एकजुट और मजबूत रहना होगा। कीव पहुंचे नेताओं में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब भी शामिल थे। इसके अलावा सात देशों के

प्रधानमंत्री और तीन विदेश मंत्री भी वहां पहुंचे।

यूक्रेन अपनी लड़ाई को जारी रखने के लिए विदेशी मदद पर काफी हद तक निर्भर है। नाटो देशों ने उसे सैन्य सहायता दी है। रूस को उत्तर कोरिया, ईरान और चीन जैसे देशों से मदद मिलने की भी बात कही जा रही है। इस युद्ध का असर दुनिया के कई देशों पर पड़ा है। खाद्यान्न की कमी, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता जैसी समस्याएं भी बढ़ी हैं। गौरतलब है कि यूक्रेन के पुनर्निर्माण की लागत बहुत भारी बताई जा रही है। विश्व बैंक, यूरोपीय आयोग और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार अगले दस साल में यूक्रेन को फिर से खड़ा करने के लिए करीब 588 अरब डॉलर की जरूरत होगी। यह रकम यूक्रेन की पिछले साल की कुल अर्थव्यवस्था से लगभग तीन गुना ज्यादा है। कुल मिलाकर, चार साल बाद भी यह युद्ध खत्म होने के कोई साफ संकेत नहीं दिख रहे हैं। यूरोप और दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या कूटनीतिक कोशिशें इस लंबे और विनाशकारी संघर्ष को खत्म कर पाएंगी।

NOTICE:

Times of Pedia does not guarantee, directly or indirectly, the quality or efficacy of any product or services described in the advertisements or other material which is commercial in nature in this Newspaper. Furthermore, Times of Pedia assumes no responsibility for the consequences attributable to inaccuracies or errors in the printing of any published material from the news agencies or articles contributed by readers. It is not necessary to agree with the views published in this Newspaper. All disputes to be settled in Delhi Courts only.

ईरान का सैन्य हेलीकॉप्टर क्रैश, चार की मौत

तेहरान: मेरिका साथ जारी भीषण तनाव के बीच मंगलवार को ईरान के मध्य भाग में एक सैन्य हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। मध्य ईरान के फल और सब्जी बाजार में यह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कम से कम चार लोगों की मौत होने की रिपोर्ट है। अमेरिका साथ जारी भीषण तनाव के बीच मंगलवार को ईरान के मध्य भाग में एक सैन्य हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। मध्य ईरान के फल और सब्जी बाजार में यह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कम से कम चार लोगों की मौत होने की रिपोर्ट है। ईरानी राज्य टेलीविजन के अनुसार यह



हादसा ईरान की राजधानी तेहरान से लगभग 330 किलोमीटर (205 मील) दक्षिण में इस्फहान प्रांत के दोर्वेह शहर में हुआ। ईरानी वायुसेना का एयरबेस इस्फहान के करीब स्थित है। यह ईरान का प्रमुख परमाणु स्थल है। अमेरिका ने जून में ईरान-इजरायल युद्ध के दौरान इसी परमाणु स्थल पर हमला किया था। इसके

अलावा फोर्दों और नतान्ज न्यूक्लियर साइट पर भी बम गिराया था। राज्य टीवी के अनुसार सेना का हेलीकॉप्टर उस वक्त दुर्घटना का शिकार हुआ, जब वह प्रशिक्षण उड़ान पर था। इस दुर्घटना में पायलट और सह-पायलट की मौत हो गई। बाजार से हेलीकॉप्टर का मलबा और धुआं उठता हुआ फुटेज सामने आया है। ईरान की

अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी फार्स ने बताया कि बाजार में जमीन पर मौजूद दो लोगों की मौत हुई। यह ईरान में एक सप्ताह से कम समय में हुई दूसरी दुर्घटना है। पिछले दिनों ईरान के पश्चिमी शहर हमदान के पास एक एफ-4 फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें एक पायलट की मौत हुई थी। ईरान में घातक दुर्घटनाओं का इतिहास रहा है। पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण ईरान में विमानों के लिए पार्ट्स की आपूर्ति सूख गई है। ईरान अपनी सरकार और कमर्शियल एयरलाइंस दोनों के लिए पुराने हेलीकॉप्टरों और विमानों के बेड़े पर निर्भर है।

New Delhi declaration 2026: five pillars for a resilient and United Asia-Pacific

Aapu Organises international conference on sustainable development and peace in asia pacific

Proposes 'Strategic Hooks' conference to be converted into a formal for governments in the asia-pacific



Group photo of the Inaugural Session, Chaired by the President, Mr J S Saluja the Chief Guest Ms Meenakshi Lekhi besides Dr Sandeep Marwah, Dr Subhash Goyal, Mr R K Chaudhary, Chairperson, Joint Electricity Regulatory Commission, Govt of Jammu & Kashmir and Laddakh.

New Delhi: Association for Asia Pacific Union (AAPU)

tive action, mutual respect and shared prosperity across the

hardship India endured in providing shelter and sustenance during that critical period.

He expressed hope that the new Government of Bangladesh will recognize the importance of maintaining strong and constructive relations with India across all sectors. He added that, as a former diplomat, he stands with AAPU and is ready to contribute in any way possible to help strengthen and shape future bilateral relations in a more positive direction.

H.E. Ms. Mahishini Colonne, High Commissioner of Sri Lanka; Ambassador K. P. Fabian, Chairman; Dr. Sudhir Mishra of DRDO, Shri Manu Srivastava (IAS), Additional Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh, Dr B R Jain, Dr. B. Sivaramappa, Dr. S. N. Mishra, Dr. A. K. Gupta; Mr. Madhok, Dr. K. K. Sharma, and Mr. Ali Mustafa also graced the function and shared their valuable remarks on the occasion.

The conference deliberated on the following proposals

THE NEW DELHI PROPOSAL ON ASIA-PACIFIC UNITY (2026)

A Framework for Collective Action and Sustainable Prosperity.

PREAMBLE: WE, the representatives of the Asia-Pacific nations, following the Asia-Pacific Union

(AAPU) conference in Feb 2026 in New Delhi, recognise that our region home to 60% of the global population stands at a historic crossroads.

Acknowledging that isolated responses to global crises are no longer sufficient, we hereby propose to convey the following Five Pillars of Implementation:

ARTICLE I: The Health & Climate Resilience Network

We propose to move beyond dialogue toward a Regional Health Security Protocol.

Proposed Action: To establish a "Green Health Corridor" facilitating the exchange of telemedicine technology and pandemic preparedness strategies between member nations.

Proposed Implementation:

Development of a shared database for disaster response and climate mitigation strate-

gies to protect vulnerable coastal and rural populations.

ARTICLE II: Digital Literacy and Technical Integration

Given the "Digital Divide" as a barrier to growth, we propose to foster cross-border technological cooperation.

Proposed Action: To standardise "Digital Literacy Certification" across borders to allow for a mobile and skilled regional workforce.

Proposed Implementation:

Facilitating private-public partnerships to extend high-speed digital infrastructure to

development of mutually beneficial trade terms.



Chief Guest Ms Meenakshi Lekhi addressing the International Conference

organised an International conference at India international centre, New Delhi on 21st Feb 2026.

The theme of the conference was "Sustainable development and peace by unity among Asia-Pacific countries with focus on media, art and culture, climate change and health." It was attended by dignitaries across the Globe.

JS Saluja, President, AAPU in his welcome address said that day is not far off when all develop developing countries of Asia Pacific will unite and 'we'll have Asia Pacific Union really like European Union and African Union.'

region.

Speaking on the occasion Dr, Sandeep Marwah, Founder Film City Noida, Chairman Marwah Studio and Petron AAPU called upon people to nurture good thinking so that we can do good deeds through our good karmas. "We would love to convert this earth into heaven, this is what I believe. I'm sure you will also believe in the same," he added.

Chief guest of the conference, Meenakshi Lekhi former Minister Of State said that, concept of AAPU for uniting the Asia Pacific Region is fantastic but this needs to be carried forward by the next gen-



Bangladesh Ambassador HE Mr Saiful M Hoque addressing the International Conference.

He further stated that for uniting we must focus on media, art, culture, climate change, health and this is theme of the Conference.

Dr. Subhash Goyal elaborated on the vision, aims, and long-term objectives of the Association for Asia Pacific Union (AAPU). He emphasized AAPU's focus on collaborative development in areas such as trade, technology, climate resilience, health security, and cultural exchange, highlighting its mission to create a structured platform for collec-

eration.

She asked the organizers to coordinate with some universities or a school of journalism to carry forward this generational idea.

Addressing the conference, Ambassador Dr. M. Saiful Haque delivered an emotional statement, expressing his deep gratitude to India for its role in the birth of Bangladesh. He acknowledged that around 18,000 Indian soldiers sacrificed their lives for Bangladesh and noted with appreciation the immense support and

remote Global South communities.

ARTICLE III: The "Canopy Collective" for Regional Stability

We proposed to advocate regional cooperation based on mutual respect and non-alignment from external power blocs.

Proposed Action: To promote the "Canopy Collective" as a platform for peaceful dispute resolution and shared



maritime and border security intelligence.

Proposed Implementation: Quarterly Track-II diplomatic briefings hosted by the AAPU Secretariat to maintain regional Peace.

ARTICLE IV: Shared Prosperity and Coercion-Free Trade

We propose to emphasise economic sovereignty and the

reliance on high-interest external debt.

Proposed Implementation: Establishment of an AAPU Business Council to connect SMEs (Small and Medium Enterprises) across Asia-Pacific borders.

ARTICLE V: Cultural and Media Ethics Alliance

To combat misinformation and preserve our unique heritage, we propose to promote "Unity Through Culture." **Proposed Action:** To launch a regional Media Ethics Forum that counters divisive narratives and promotes the shared values of the Global South.

Proposed Implementation: Annual cultural exchange programs and collaborative art initiatives to strengthen the "human link" between our nations.

COMMITMENT TO PERMANENCY

By agreeing to these proposals, we, the Asia-Pacific Countries, should recommend establishing a Permanent AAPU Secretariat in New Delhi to monitor the progress of these articles and serve as a consultative body for participating governments.

Evaluating Indian Kings: Tipu Sultan



Prof. Ram Puniyani

Tipu Sultan has been in the news quite often particularly in Karnataka, more so on the occasions of state sponsored celebrations of his birth anniversary. There, BJP regularly creates obstacles to these celebrations and ruckus is usually the result. This time around he is in the news from Maharashtra, Malegaon. As the newly elected deputy mayor of Malegaon Shan-e-Hind Nihal Ahmad had put up the portrait of Tipu Sultan in her office, the Shiv Sainiks noticed that. They got it removed through the intervention of authorities. Some protests were also held. Following this the Maharashtra Pradesh Congress Committees President Harshvardhan Sapkal expressed his opinion against removal of this portrait saying that the contributions of Tipu Sultan to Mysore are equivalent to that of Chhatrapati Shivaji Maharaj in Maharashtra. This statement was opposed by the state Chief minister Devendra Fadnavis. Fadnavis said that comparing Tipu to Shivaji Maharaj is an insult to Maharaj. Following this Congress office was stoned by BJP workers and nearly 7 people were injured in the mayhem created by this.

The objection of BJP to

Sapkal's statement is that Tipu was a mass murderer of Hindus, he tried to convert Hindus to Islam. There are many other charges put against Tipu by the Hindu Nationalists. Most of these try to project Tipu as Anti-Hindu and a cruel king. This is far from the truth. Lots of these myths are part of communal narrative accentuated by the British Narratives which are harsher against Tipu in particular. This is due to the fact that he was one of the kings who fought against the British. Tipu had asked Nizam and Peshwas to oppose the armies of East India Company. He foresaw the dangers of British power entrenching in India.

His administration was a mixed one with many top officers being Hindus. Purnaiah served him as the Mir Miran (head of a department) and was crucial to his administration. Krishna Rao was his treasurer. Shamaiya Iyengar held a high-ranking ministerial position and Narsimha Iyengar held a position in the postal department. Tipu Sultan reportedly provided grants to the Sringeri Shankaracharya, including for the rebuilding of the temple and the installation of the goddess Sharada. He granted land and endowments to various temples throughout his kingdom. During his reign, the ten-day Dussehra celebrations were an integral part of the social life of Mysore.

In 1791, Maratha forces led by Raghunath Rao Patwardhan attacked and plundered the historic Sringeri Sharada

Peetham, causing the Shankaracharya to flee. Upon learning of this, Tipu Sultan expressed deep anger, stating that those who committed such acts would face consequences, and promptly sent funds, gifts, and letters to restore the temple and reconsecrate the idol. The raid was part of the Third Anglo-Mysore War, during which Maratha forces caused significant destruction to the temple complex, including killing or wounding people and looting property. Tipu Sultan, who frequently corresponded with the Sringeri Jagadguru and addressed him with high respect, immediately ordered the Mysore administration to assist in the restoration, demonstrating his patronage of certain Hindu institutions. Evidence of this restoration is found in several letters in Kannada, preserved in the Sringeri monastery records, where Tipu requested the Jagadguru to pray for the prosperity of his kingdom.

He was a staunch opponent of the British. There is an accusation against him that he persecuted some Hindu and Christian communities. The reason for this persecution however was purely political not religious. About these persecutions historian Kate Brittlebank says that "This was not a religious policy but one of chastisement". The communities targeted by him were seen as disloyal to the state. The communities he targeted did not belong only to Hindu stream. He also acted against some Muslim communities like the

Mahdavis. The reason was that these communities were in support of the British and were employed as horsemen in the East India Company's armies. Another historian Susan Bayly says that his attack on Hindus and Christians outside his state is to be seen on political grounds as at the same time he had developed close relations with these communities within Mysore.

Sarfraz Shaikh in his book 'Sultan-E-Khudad' has reproduced the 'Manifesto of Tipu Sultan' in which he declares that he would not discriminate on religious grounds and would protect his empire until his last breath. He had great interest in Rocket technology. This finds appreciative mention in A.P. J Abdul Kalam's book 'Wings of fire'.

It is interesting to note in the RSS series for children on Indian History, they had published a book on Tipu in the 1970s. BJP's Yeddyurappa had adorned Tipu's headgear to solicit votes in 2010 elections in Karnataka. Indian President Ramnath Kovind sent a eulogising message on the occasion of Tipu Jayanti (2017). He has an RSS background. He praised Tipu by saying that "Tipu Sultan died a heroic death fighting the British. He was also a pioneer in the development and use of Mysore rockets in warfare." Tipu's photo adorns our Constitution (Original handwritten copy signed by the framers) in part XVI page 144 along with Rani Laxmibai as those who

fought against British.

Due to his policies, he was popular among the people of Mysore. There are many folk songs, sung in villages, praising him. It is for this reason that one of our greatest playwrights Girish Karnad said that had Tipu been a Hindu, he would have the same status that Shivaji Maharaj has in Maharashtra. This is very close to what Sapkal stated, nothing extra.

This whole incident of opposing the portrait of Tipu, in Deputy mayors' office is one more instance of communal forces latching on to divisive politics. Kings should not be seen just by their religion, their policies towards people of different religions and people's welfare should be the major criterion for evaluating them. Tipu stands very tall in this scale of religious tolerance. The half-baked propaganda of the communal forces is trying to divide communities.

The major tribute to Tipu was paid by Subhash Chandra Bose. He adopted Tipu's 'springing tiger' as the insignia of Azad Hind Fauz, which fought against the British. The major contribution of Tipu was to forewarn the Indian Kings about the advancing threat of the East India Company, the British. It was for this that he bravely fought against the British and laid down his life in the fourth Anglo Mysore War. The communal forces who are out to demonise Tipu belong to the ideology which did not even a little finger against British rule.

Syed Sadatullah Husaini Calls for Deeper Piety and Steadfastness in Ramadan 2026 Message

New Delhi: The President of Jamaat-e-Islami Hind (JIH), Syed Sadatullah Husaini has called upon Muslims to treat Ramadan 2026 as a serious project of inner reform and principled living, stressing that fasting is meant to cultivate piety, patience, and moral strength at a time when faith and values face constant pressure.



In a statement to the media, the JIH President said, "Piety is a state of the heart, a deep consciousness of Allah's presence and His oversight, which creates hesitation toward sin and a natural attraction toward virtue." He explained that fasting trains believers to live

with this awareness beyond rituals and outward discipline. Highlighting the spiritual dimension of fasting, he said that through fasting a person becomes acquainted with spiritual pleasures as opposed to physical ones, and that hunger and restraint reveal that

bodily comfort does not define a meaningful life. Repentance and seeking forgiveness, he added, cleanse the soul and restore clarity of purpose. Syed Sadatullah Husaini described Ramadan as the 'Month of Patience' and said, "Patience is the name for remaining as

firm as a mountain on one's principles against all external forces and internal promptings." He noted that fasting teaches restraint amid hunger, thirst, workload, and distraction, ensuring that actions flow from principle rather than impulse. By altering sleep,

food habits, and daily routines for the sake of Allah, believers develop willpower and the strength to make difficult choices and remain steadfast under pressure.

The President of Jamaat-e-Islami Hind averred that faith and morals are facing continuous challenges through social media and the spread of immodesty, and that values and principles are under tremendous pressure in the digital age. He urged Muslims to move beyond symbolic observance and allow Ramadan to become a turning point that produces lasting personal and collective reform rooted in piety and steadfastness.

SUBSCRIPTION FORM TIMES OF PEDIA

Issue	Subscription Price	Years
52	250/-	1
104	500/-	2
260	1,300/-	5
520	2,600/-	10
--	5,000/-	Life

Name :
 Address :

 Email:.....
 Contact Phone No.....
 for donation /life /10 yrs /5 yrs subscription
 The sum of Rupees..... (Rs...../-)
 through cheque/DD No.....dt.....

Fill the above form neatly in capital letters and send it to us on the following address :
 Times of Pedia, K-2-A-001, Abul Fazal Enclave-I,
 Jamia Nagar, Okhla, New Delhi-110025
 or email : timesofpedia@gmail.com

Also Send us your subscription, membership, donation amount in favour of Times of Pedia, New Delhi
 Punjab National Bank, Nanak Pura Branch,
 New Delhi-110021
 A/C No.1537002100017151, IFS Code : PUNB 0153700



“First, they ignore you, then they laugh at you, then they fight you and then you win.”

- Mahatma Gandhi

ADVERTISEMENT TARIFF TIMES OF PEDIA

Size/Insertion Single	B&W (Rs)	4 Colour (Rs)
Full Page (23.5 x 36.5 cm)	30,000/-	1,00,000/-
A4 (18.7 x 26.5 cm)	20,000/-	60,000/-
Half Page (Tall-11.6 x 36.5 cm)	18,000/-	50,000/-
Half Page (wide-23.5 x 18 cm)	8,000/-	50,000/-
Quarter Page (11.6 x 18 cm)	10,000/-	28,000/-
Visiting Card size (9.5 x 5.8 cm)	3,000/-	10,000/-

MECHANICAL DATA:

Language: English, Hindi and Urdu

Printing: Front and Back - 4 Colours , Inside pages - B&W

No. of Pages: 12 pages (more in future)

Price: Rs. 3/-

Print order: 25,000

Periodicity: Weekly

Material details: Positives/Format of your advertisements should reach us 10 days before printing.

Note: 50% extra for back page, 100% extra for front page

Please Add Rs. 10 for outstation cheques.

50% advance of total add cost would be highly appreciable, in case of one year continue add. Publication cost will reduce 50% of actual cost.

Bank transactions details of TIMES OF PEDIA

Send your subscriptions/memberships/donations etc.

(Cheques/DD) in favour of TIMES OF PEDIA New Delhi

Punjab National Bank, Nanak Pura Branch , New Delhi-110021

A/C No.1537002100017151, IFS Code : PUNB 0153700

नाश्ते में बनाएं प्रोटीन से भरपूर मूंग दाल-अंडा चीला

नई दिल्ली। आज हम आपको नाश्ते में प्रोटीन-रिच मूंग दाल अंडा चीला बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे। इसे बनाना बेहद आसान है और इसका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि एक बार खाने के बाद आपको बार-बार बनाने का मन करेगा।

अगर आप नाश्ते में कुछ हेल्दी, टेस्टी और जल्दी बनने वाला खाना चाहते हैं, तो मूंग दाल अंडा चीला जरूर ट्राई करें। मूंग दाल प्रोटीन, फाइबर, पोटेसियम और मैग्नीशियम से भरपूर होती है जो लंबे समय तक पेट को भरा रखने, डाइजेशन बेहतर करने और वजन घटाने में मदद करती है। वहीं, अंडा अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन, विटामिन और मिनरल प्रदान करता है जो एनर्जी बढ़ाता है मसल्लस को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है।

मूंग दाल और अंडे को मिलाकर बनाया गया यह चीला शरीर को एनर्जी देता है और



लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता है। खास बात यह है कि आप इसे सुबह की जल्दबाजी में आसानी से बना सकते हैं। आज इस खबर में हम आपको मूंग दाल अंडा चीला बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे बच्चों से लेकर बड़ों तक सब पसंद करेंगे।

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई ऐसा नाश्ता चाहता है जो जल्दी बन जाए, पेट भी भरे और शरीर को भरपूर पोषण भी दे। ऐसे में मूंग दाल अंडा चीला एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभर रहा है। यह न केवल प्रोटीन

से भरपूर है, बल्कि स्वाद में भी इतना लाजवाब है कि एक बार खाने के बाद इसे बार-बार बनाने का मन करता है।

अगर आप सुबह के नाश्ते में कुछ हेल्दी, टेस्टी और जल्दी बनने वाला व्यंजन तलाश रहे हैं, तो मूंग दाल अंडा चीला जरूर ट्राई करें। यह रेसिपी खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो फिटनेस का ध्यान रखते हैं, वजन नियंत्रित रखना चाहते हैं या दिनभर ऊर्जावान बने रहना चाहते हैं।

मूंग दाल को भारतीय रसोई में हमेशा से ही पौष्टिक आहार के रूप में जाना जाता है। इसमें

प्रोटीन, फाइबर, पोटेसियम, मैग्नीशियम और कई जरूरी विटामिन मौजूद होते हैं। फाइबर की अच्छी मात्रा पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में मदद करती है और लंबे समय तक पेट भरा होने का एहसास देती है। यही कारण है कि इसे वजन घटाने वाले डाइट प्लान में भी शामिल किया जाता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि सुबह के समय प्रोटीन और फाइबर से भरपूर भोजन लेने से दिनभर अनहेल्दी स्नैकिंग की आदत कम होती है। मूंग दाल का सेवन ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखने में भी सहायक माना जाता है।

अंडा उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है। इसमें विटामिन बीक्यू, विटामिन डी, आयरन और सेलेनियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अंडा शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है और मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है।

खेल समाचार

T20 वर्ल्ड कप: कैसे खुलेगा सेमीफाइनल का दरवाज़ा?



टी 20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के लिए अब हर मैच नॉकआउट जैसा हो गया है। सिर्फ जीत काफी नहीं, बल्कि जिम्बाब्वे पर बड़ी जीत से ही नेट रन रेट सुधर सकता है। टीम कॉम्बिनेशन, ओपनिंग पर मंथन जारी है। अगला मुकाबला भारत के अभियान की दिशा तय कर सकता है।

20 वर्ल्ड कप अभियान अब बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच गया है। सुपर-8 में मिली भारी हार के बाद सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम को सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए सिर्फ जीत नहीं, बल्कि बड़ी जीत की दरकार है।

26 फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबला अब औपचारिक मैच नहीं, बल्कि 'मैथमेटिकल सर्वाइवल टेस्ट' बन चुका है। सुपर-8 में साउथ अफ्रीका से मिली हार ने भारत का नेट रन रेट गिराकर -3.800 कर दिया है, जिससे वह पाइंट टेबल में पीछे खिसक गया।

वहीं वेस्टइंडीज (+5.350) और साउथ अफ्रीका (+3.800) बेहतर रन रेट के साथ आगे चल रहे हैं। ऐसे में अगर तीनों टीमों समान अंकों पर भी पहुंचती हैं, तो फैंसला रन रेट से होगा, और फिलहाल भारत इस गणित में काफी पीछे है।

अगर भारत पहले बल्लेबाजी करते हुए 220 रन बनाता है, तो उसे विपक्ष को 120 या उससे कम पर रोकना होगा। यानी 100 रन या उससे ज्यादा का अंतर ही वह झटका देगा, जिससे भारत का रन रेट दोबारा मुकाबले में आ सके। साधारण जीत अब किसी काम की नहीं, बल्कि भारत को मैच 'डॉमिनेट'

करना होगा।

अहमदाबाद में भारत की भारी हार ने समीकरण बदल दिए। अगर साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज और भारत सभी चार पाइंट्स पर खत्म होते हैं। वहीं अगर भारत जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज को हरा देता है, जबकि साउथ अफ्रीका एक गेम हार जाता है, तो यह बहुत मुमकिन है, NRR तय करेगा कि कौन आगे बढ़ेगा। अभी, भारत बहुत पीछे चल रहा है।

यदि जिम्बाब्वे पहले बैटिंग करे और टारगेट दे, तो क्या करना होगा? अगर भारत चेज करता है, तो सेमीफाइनल की उम्मीदें बचाने के लिए बहुत तेज चेज करना होगा। NRR सुधारने के लिए जिम्बाब्वे अगर 150-160 रन बनाए, तो भारत को वो टारगेट 11-12 ओवर में चेज करना चाहिए, यानी 150 रन 11 ओवर में चेज करने पर NRR में बड़ा बूस्ट मिलेगा। वहीं सामान्य रूप से, 100+ रनों की जीत या इससे ज्यादा मार्जिन चाहिए।

लगातार विफलताओं के बाद अभिषेक शर्मा की जगह संजू सैमसन को मौका देने की मांग तेज हो गई है। टीम मैनेजमेंट पावरप्ले में 70+ रन के आक्रामक लक्ष्य पर विचार कर रहा है, ताकि मैच शुरुआत से ही एकतरफा बनाया जा सके।

चेपांक की पिच और स्पिन बनेगा भारत का हथियार मुकाबला एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां पारंपरिक रूप से स्पिनरों को मदद मिलती है। ऐसे में भारत तीन-प्रमुख स्पिन विकल्पों के साथ उतर सकता है। इमें कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल शामिल हैं।

बासी रोटी के फायदे: सेहत के लिए वरदान या नुकसान?

नई दिल्ली। अक्सर भारतीय घरों में रात की बची हुई रोटी सुबह खाने खा ली जाती हैं। इसके पीछे अलग-अलग तर्क होते हैं, जैसे इतनी जल्दी रोटी खराब नहीं होती, बासी रोटी सेहत के लिए अच्छी होती है, आदि। लेकिन आज सेहत को देखते हुए कई लोग जहां लोग कुछ घंटों पुराना खाना खाने से बचते हैं तो ऐसे में रात की रोटी अगले दिन सुबह खाना सेहत के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक?

अमेरिकन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन की रिसर्च बताती है कि बासी रोटी में कुछ खास पोषक तत्व बढ़ जाते हैं इसलिए ये हेल्दी होती है। वहीं कुछ नई स्टडीज बताती हैं कि सही तरह से रखी गई बासी रोटी में रेजिस्टेंट स्टार्च बनता है, जो पाचन और ब्लड शुगर के लिए फायदेमंद माना जा रहा है।

रिपोर्ट भी दादी-नानी की बात को साबित करती हैं कि बासी रोटी पेट के लिए अच्छी होती हैं। रिसर्च के मुताबिक ठंडी या बासी रोटी में कार्बोहाइड्रेट की संरचना बदल जाती है जिस कारण वो धीरे-धीरे डाइजैस्ट होती है और आपको लंबे समय तक एनर्जी मिलती रहती है।

कई विदेशी वेबसाइट्स और



न्यूट्रिशन आर्टिकल्स में दावा किया गया है कि बासी रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ताजी रोटी से कम होता है। इसका मतलब है कि बासी रोटी शरीर में धीरे-धीरे शुगर रिलीज करती है जिससे अचानक से स्पाइक नहीं होता। वहीं कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि यदि इसे सीमित मात्रा में लिया जाए तो डायबिटीज और प्री-डायबिटिक पैशेंट को फायदा हो सकता है। कब्ज में राहत और मेटाबॉलिज्म सुधार के लिए फायदेमंद माना गया है। रेजिस्टेंट स्टार्च को प्रीबायोटिक माना जाता है यानी ये आंतों के अच्छे बैक्टीरिया के लिए खाना है। वहीं बासी रोटी में यही रेजिस्टेंट स्टार्च बढ़ जाता है जो कि पेट के लिए फायदेमंद है।

लाइफस्टाइल वेबसाइट्स का कहना है कि बासी रोटी खाने से पेट देर तक भरा महसूस करता है क्योंकि बासी

रोटी का डाइजेशन धीमा होता है और इसमें फाइबर अधिक होता है। इससे आप ओवरईटिंग से बचते हैं और पोर्शन कंट्रोल में मदद मिलती है। ऐसे में आपको वजन कंट्रोल करने में भी मदद मिल सकती है।

रिपोर्ट कहती हैं कि बासी रोटी खाने के फायदे तभी तक हैं जब रोटी सही तरह से स्टोर की गई हो और क-क घंटे के अंदर खा ली जाए। एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि ज्यादा समय तक बाहर रखी रोटी में बैक्टीरिया और फफूंद पनप सकते हैं जो फूड पाइजनिंग, पेट दर्द, उलटी और इंफेक्शन का कारण बन सकते हैं। इसलिए हल्की सी भी बदबू या दाग दिखे तो तुरंत फेंक देना चाहिए। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स की राय साफ है। ताजी रोटी हमेशा पहला ऑप्शन होनी चाहिए लेकिन कभी-कभार सही तरह से रखी गई रात की

रोटी सुबह खा लेना ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित है। अगर आपको डायबिटीज, गैस या स्टमक सेंसिटिव है तो डॉक्टर या डाइटीशियन से पूछकर ही ये खाएं।

भारतीय घरों में अक्सर रात की बची हुई रोटी को अगले दिन सुबह खा लिया जाता है। इसके पीछे कई तर्क दिए जाते हैं—जैसे रोटी इतनी जल्दी खराब नहीं होती या बासी रोटी सेहत के लिए फायदेमंद होती है। लेकिन बदलती लाइफस्टाइल और सेहत के प्रति बढ़ती जागरूकता के बीच यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या रात की रोटी सुबह खाना वाकई सही है? सीमित मात्रा में इसका सेवन प्री-डायबिटिक या डायबिटीज के मरीजों के लिए लाभकारी हो सकता है, हालांकि इस संबंध में व्यक्तिगत सलाह जरूरी है।

भारतीय पारंपरिक ज्ञान में भी बासी रोटी को फायदेमंद बताया गया है। ग्रामीण इलाकों में लोग बासी रोटी को दूध या पानी के साथ खाते हैं और इसे पेट के लिए अच्छा मानते हैं। आधुनिक शोध भी कुछ हद तक इस मान्यता का समर्थन करते दिखाई देते हैं, खासकर रेजिस्टेंट स्टार्च के संदर्भ में।

باکردار مسلمان ایک ذمہ دار ہندوستانی شہری



غنیف احسن

ہندوستان کے موجودہ تناظر میں اکثر یہ غلط بیانی کی جاتی ہے کہ اسلام سے وفاداری اور وطن (ہندوستان) سے وفاداری دو متضاد جذبے ہیں۔ جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، اسلامی تعلیمات اور ہندوستانی دستور دونوں ایک ایسا ڈھانچہ فراہم کرتے ہیں جہاں ایک شخص بیک وقت ایک بہترین مومن اور ایک مثالی محب وطن شہری بن کر زندگی گزار سکتا ہے۔ اسلامی روایت میں ”حب الوطن من الایمان“ (وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے) ایک ایسی بنیاد ہے جو مومن کے کردار کو جلا بخشتی ہے۔ ایک ہندوستانی مسلمان کے لیے یہ ملک محض ایک جغرافیائی خطہ نہیں، بلکہ اس کے آباؤ اجداد کی سرزمین، اس کی تاریخ کا امین اور اس کے مستقبل کا ضامن ہے۔ اسلام سکھاتا ہے کہ جو

انسانوں کا شکر گزار نہیں، وہ خدا کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ جس زمین کا ہم اناج کھاتے ہیں اور جہاں کی فضاؤں میں ہم سانس لیتے ہیں، اس کی ترقی کے لیے مخلص رہنا دراصل ایک دینی تقاضا ہے۔ ہندوستان صوفیاء اور اولیاء کی سرزمین ہے جنہوں نے یہاں کی کثیر الثقافتی مٹی میں انسانیت اور محبت کے بیج بونے۔ ایک مسلمان کے لیے اپنے ملک کی مٹی سے لگاؤ اس کی روحانی شناخت کا حصہ ہے۔ اسلام اپنے پیروکاروں کو ”عہد“ کی پاسداری کا سختی سے حکم دیتا ہے۔ جب ایک مسلمان ہندوستان میں رہتا ہے، تو وہ ریاست کے ساتھ ایک سماجی اور آئینی معاہدے میں بندھا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا واضح کاف اعلان ہے ”اے ایمان والو، اپنے معاہدوں کو پورا کرو“ (سورۃ المائدہ: 1)۔ ہندوستانی دستور کی وفاداری دراصل اسی قرآنی حکم کی تعمیل ہے۔ اسلامی فقہ کا اصول ہے کہ مسلمان جس ملک کے شہری ہوں، وہاں کے اخلاقی قوانین کی پابندی ان پر لازم ہے، بشرطیکہ وہ قوانین انہیں معصیت (گناہ) پر مجبور نہ کریں۔ چونکہ ہندوستانی آئین (آرٹیکل 25) شہریوں کو مذہبی آزادی کی ضمانت دیتا ہے، اس لیے یہاں مذہب اور ملک کے قانون کے درمیان کوئی ٹکراؤ باقی نہیں رہتا۔ نبی کریمؐ نے پڑوسیوں کے حقوق پر اس قدر زور دیا ہے کہ صحابہ کرام کو لگایا ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں حصہ دار نہ بنا دیا جائے۔ ایک کثیر مذہبی

ملک میں یہ تعلیمات ”گنگا جمنی تہذیب“ کی بنیاد بنتی ہیں۔ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے انسان (خواہ وہ کئی بھی مذہب کے ہوں) محفوظ رہیں۔ عبادت صرف نماز و روزہ تک محدود نہیں، بلکہ اللہ کی مخلوق کی خدمت بھی عبادت ہے۔ ملک میں تعلیمی، معاشی اور سماجی بہتری کے لیے کام کرنا ”خیر الناس من ینفع الناس“ (بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے) کی عملی تصویر ہے۔ یہ تصور کہ اسلام اور حب الوطنی ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک مفطقی مغالطہ ہے حالانکہ امانت داری ایک دینی فریضہ ہے جبکہ تیس کی ادائیگی اور سرکاری املاک کی حفاظت ایک شہری ذمہ داری ہے جس کے نتیجے میں مستحکم اور خوشحال معیشت کا حصول ہوتا ہے۔ اسی طرح عدل و انصاف ایک دینی فریضہ ہے جبکہ مظلوم کا ساتھ دینا اور قانون کا احترام ایک شہری ذمہ داری ہے جس کے نتیجے میں پر امن اور منصفانہ سماج کا قیام ہوتا ہے۔ حصول علم ایک دینی فریضہ ہے جبکہ سائنس، ٹیکنالوجی اور آرٹ میں مہارت ایک شہری ذمہ داری ہے جس کے نتیجے میں ملک کی عالمی سطح پر ترقی عمل میں آتی ہے۔ ہندوستان کی طاقت اس کے تنوع میں ہے، جہاں مذہبی شناخت قومی شناخت کو کمزور نہیں بلکہ توانا بناتی ہے۔ ایک ”اچھا مسلمان“ اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر ایک شخص دیانتدار، رحم دل اور قانون کا پابند ہے، تو وہ بیک

وقت اپنے رب کا بھی فرمانبردار ہے اور اپنے ملک کا بھی وفادار ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: یا ایہذا الذین آمنوا اوفوا بالعقود (اے ایمان والو! اپنے عہد و پیمانہ کو پورا کرو۔) (سورۃ المائدہ: 1) اسلام محض چند عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل ضابطہ ہے۔ ایک مسلمان جہاں اپنے رب کا بندہ ہے، وہیں وہ اس معاشرے اور ملک کا ایک ذمہ دار شہری بھی ہے جہاں وہ رہتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جس مٹی نے ہمیں پناہ دی، جس کا اناج ہم کھاتے ہیں اور جہاں ہم امن و سکون سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس زمین سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ہمارے نبی کریمؐ جب مکہ سے ہجرت کر رہے تھے، تو آپؐ نے مکہ کی طرف مڑ کر دیکھا اور فرمایا تھا: ”اے مکہ! تو مجھے تمام شہروں سے عزیز ہے، اگر تیرے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں کہیں اور نہ جاتا۔“ یہ ایک وطن سے محبت کا فطری اور دینی اظہار تھا۔ ہندوستان کا دستور ہمیں اپنی مذہبی شناخت برقرار رکھنے کی آزادی دیتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ہمارا ملک کے ساتھ ایک ”عہد“ ہے کہ ہم اس کے قوانین کی پاسداری کریں گے۔ نبی کریمؐ نے مدینہ منورہ میں ”بیثاق مدینہ“ کے ذریعے مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ صلہ کر رہنے کا جو نمونہ پیش کیا، وہ آج کے جمہوری نظام میں بھائے باہم

کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ملک کے وسائل، سڑکیں، بجلی، پانی اور سرکاری املاک یہ سب ہماری اجتماعی امانت ہیں۔ ان کو نقصان پہنچانا یا قانون کی خلاف ورزی کرنا شرعی طور پر ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کے رسولؐ نے فرمایا: ”مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان (اور انسان) محفوظ رہیں۔۔۔“ ہمارا دین ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ جب ایک مسلمان نوجوان ڈاکٹر، انجینئر یا سائنسدان بن کر ملک کی خدمت کرتا ہے، تو وہ دراصل اسلام کی سر بلندی کا باعث بنتا ہے۔ اپنے غیر مسلم پڑوسیوں کے دکھ درد میں شریک ہونا، غریبوں کی مدد کرنا اور ملک میں امن و امان قائم رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دینا صدقہ جاریہ ہے۔ ہمارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں کہ اگر ایک مسلمان ایسا ایماندار اور محب وطن ہے، تو اس کا دین کتنا عظیم ہوگا۔ ہمیں اس مفنی پروپیگنڈے کا جواب اپنے عمل سے دینا ہے کہ ایک مسلمان اپنے ملک کا وفادار نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، اسلام ہمیں ”خیر خواہی“ سکھاتا ہے۔ آج کے دور میں ایک اچھا مسلمان اور ذمہ دار شہری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں صاف اول میں رہیں، سوشل میڈیا پر نفرت انگیزی کے بجائے امن اور سچائی کو فروغ دیں، فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ پڑوسیوں کو اسلام کا حقیقی چہرہ نظر آئے۔

مائیکرو پلاسٹکس کا عالمی بحران اور حبابانی حل

ظفر اقبال

ایک سو صدی انسانی تاریخ کا وہ دور ہے جس میں ٹیکنالوجی، صنعت اور معیشت نے غیر معمولی ترقی کی ہے۔ مصنوعی ذہانت سے لے کر جینیاتی انجینئرنگ تک انسان نے فطرت کے کئی رازوں کو سمجھے اور انہیں اپنی سہولت کے لیے استعمال کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ مگر اس ترقی کی ایک قیمت بھی ہے۔ مصنوعی انقلاب کے بعد سے پیدا ہونے والی ہر شے مصنوعی اشیاء میں پلاسٹک سب سے زیادہ ہمہ گیر اور اثر انداز ایجاد ثابت ہوئی ہے۔ پلاسٹک نے انسانی زندگی کو آسان بنایا، اشیاء کو محفوظ رکھا، خوراک کو دیر پا کیا، بجلی شعبے میں انقلابی سہولتیں فراہم کیں اور صنعتوں کو کم لاگت اور زیادہ پیداوار کے قابل بنایا۔ مگر آج یہی پلاسٹک ماحولیاتی بحران کی علامت بن چکا ہے۔ پلاسٹک کی سب سے بڑی خصوصیت اس کی پائیداری ہے اور یہی خصوصیت اب ایک خطرناک خامی میں تبدیل ہو چکی ہے۔ روایتی پلاسٹک قدرتی طور پر ٹکٹے سڑنے میں 20 سے 500 سال تک لے سکتا ہے۔ اس دوران یہ ٹوٹا، بکھرتا اور چھوٹے ذرات میں تقسیم ہوتا رہتا ہے، جنہیں ہم مائیکرو پلاسٹکس کہتے ہیں۔ یہ مائیکرو پلاسٹکس اب ہماری خوراک، پانی، مٹی اور مٹی کے فضا میں بھی شامل ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام کے مطابق صرف 2020 میں تقریباً 7.7 ملین ٹن مائیکرو پلاسٹکس ماحول میں شامل ہوئے اور اندازہ ہے کہ 2040 تک یہ مقدار دو گنی ہو سکتی ہے۔ اسی بڑھتے ہوئے بحران کے تناظر میں جاپان کے سائنس دانوں نے ایک اہم پیش رفت کی ہے۔

The Matter Science اور University of Tokyo کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے ایک ایسا پودوں پر مبنی پلاسٹک تیار کیا ہے جو عام استعمال میں مضبوط رہتا ہے، مگر مین پانی میں چند گھنٹوں کے اندر مکمل طور پر تحلیل ہو جاتا ہے۔ یہ تحقیق ممتاز سائنسی جریدے Journal of the American Chemical Society میں شائع ہوئی۔ پلاسٹک کی صنعتی پیداوار بیسویں صدی کے وسط میں تیزی سے بڑھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس کی مانگ میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ ہاگوارن، مضبوط ساخت، پانی سے مزاحمت اور کم قیمت نے اسے ہر شعبے میں مقبول بنا دیا۔ آج پلاسٹک کے بغیر زندگی کا تصور تقریباً ناممکن ہے۔ خوراک کی جیکنگ، بوتلیں، تھیلیاں، طبی آلات، سرج، خون کی تھیلیاں، گاڑیوں کے پرزے، موبائل فون، کمپیوٹر، زرعی فلم، حتیٰ کہ خلائی مشینوں میں بھی پلاسٹک استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جب پلاسٹک کی پیداوار اس رفتار سے بڑھنے لگی جس کا متوازن انتظام نہیں کیا گیا۔ ری سائیکلنگ کا نظام محدود رہا اور بڑی مقدار میں پلاسٹک کچرا زمین اور سمندروں میں جمع ہونے لگا۔ ہر سال تقریباً آٹھ ملین ٹن پلاسٹک کچرا سمندروں میں داخل ہوتا ہے۔ دریا، بارش کا پانی اور نکاسی آب کے نظام اسے شہروں سے ساحلوں تک لے جاتے ہیں۔ وہاں سے یہ سمندری لہروں اور دھاروں کے ذریعے دنیا بھر میں پھیل جاتا ہے۔ مائیکرو پلاسٹکس وہ پلاسٹک ذرات ہیں جن کا سائز پانچ ملی میٹر سے کم ہوتا ہے۔ انہیں دو بنیادی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے:

1- پرائمری مائیکرو پلاسٹکس: یہ براہ راست چھوٹے سائز میں تیار کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کاسمیٹکس میں شامل مائیکرو بیڈز، صنعتی صفائی میں استعمال ہونے والے ذرات، اور مصنوعی کپڑوں کے باریک ریشے۔
2- سیکنڈری مائیکرو پلاسٹکس: یہ بڑے پلاسٹک مواد کے ٹوٹنے، گھسنے اور سورج کی لٹرا وولٹ شعاعوں کے اثر سے بنتے ہیں۔ وقت کے ساتھ پلاسٹک کی اشیاء جیسے بوتلیں، تھیلیاں اور فشنگ نیٹس چھوٹے ذرات میں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ یہ ذرات سمندروں، دریاؤں، جھیلوں، مٹی اور حتیٰ کہ ہوا میں بھی موجود ہیں۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ مائیکرو پلاسٹکس قطبین کی برف، پہاڑی علاقوں اور دور دراز جزیروں تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ صورتحال اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ مسئلہ عالمی نوعیت اختیار کر چکا ہے۔ مائیکرو پلاسٹکس کا سب سے تشویشناک پہلو ان کا خوراک کی زنجیر میں داخل ہونا ہے۔ سمندری جاندار مثلاً پلانکٹن، مچھلیاں، جھینگے اور سپ۔ انہیں خوراک سمجھ کر نگل لیتے ہیں۔ چونکہ یہ ذرات جسم میں تحلیل نہیں ہوتے، اس لیے یہ معدے میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ان جانداروں کو بڑی مچھلیاں کھاتی ہیں اور بالآخر یہ سلسلہ انسان تک پہنچتا ہے۔ تحقیقی مطالعات میں مائیکرو پلاسٹکس درج ذیل اشیاء میں پائے گئے ہیں: سمندری مچھلی، جھینگے، سمندری نمک، بوتل بند پانی، نکلے کا پانی، شہد، دودھ وغیرہ۔ بعض مطالعات کے مطابق انسانی خون اور پیچھے پھڑوں میں بھی مائیکرو پلاسٹکس کی موجودگی سامنے آئی ہے۔ اگرچہ اس موضوع پر طویل مدتی تحقیق ابھی جاری ہے، مگر ابتدائی نتائج کئی خدشات کو جنم دیتے ہیں: 1- سوزش

اور مدافعتی رد عمل، غیر ملکی ذرات جسم میں داخل ہونے پر مدافعتی نظام کو متحرک کرتے ہیں، جس سے سوزش پیدا ہو سکتی ہے۔ 2- ہارمونل نظام میں خلل: پلاسٹک میں شامل بعض کیمیائی مادے جیسے بیسفینول اے (بی پی اے) اور فٹھالٹس اینڈ وکرائن نظام کو متاثر کر سکتے ہیں۔ 3- خلیاتی نقصان: مائیکرو پلاسٹکس آکسیڈیٹو اسٹریس پیدا کر کے خلیات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ 4- ممکنہ سرطان کے امکانات: کچھ کیمیائی اجزاء سرطان کے خطرے سے منسلک کیے گئے ہیں، اگرچہ مزید تحقیق ضروری ہے۔ سمندری حیات پلاسٹک آلودگی کا سب سے بڑا شکار ہے۔ مچھلی پلاسٹک بیگز کو جلی فش سمجھ کر نگل لیتی ہیں۔ سمندری پرندے بوتلوں کے ڈھکن اور رنگین ٹکڑوں کو خوراک سمجھ لیتے ہیں۔ ذہیل مچھلیوں کے معدے سے کلو گرام کے حساب سے پلاسٹک برآمد ہوا ہے۔ مائیکرو پلاسٹکس غذائی قلت، تولیدی مسائل اور شرح اموات میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ پلاسٹک بحران کے حل کے لیے باؤڈیگرڈیٹبل پلاسٹک متعارف کرائے گئے، مگر ان میں کئی مسائل ہیں: اکثر صنعتی کمپوسٹنگ کی مخصوص شرائط میں ہی تحلیل ہوتے ہیں۔ سمندری پانی میں مکمل تحلیل نہیں ہوتے۔ ٹھنڈے اور محدود پیمانے پر دستیاب ہیں۔ اسی تناظر میں جاپانی سائنس دانوں کی نئی ایجاد اہمیت رکھتی ہے۔ جاپان میں RIKEN Center for Emergent Matter Science اور The University of Tokyo کے سائنس دانوں نے لکڑی سے حاصل کردہ سیلولوز اور نمک کے مرکبات کو ملا کر ایک نیا پلاسٹک تیار کیا۔ یہ

تحقیق Journal of the American Chemical Society میں شائع ہوئی۔ ٹیم کے سربراہ تاکو زو آئیدا کے مطابق یہ مواد عام استعمال میں مضبوط اور ٹکدار رہتا ہے، مگر ٹھیک پانی میں اس کے کیمیائی بندھن ٹوٹ جاتے ہیں اور یہ چند گھنٹوں میں مکمل تحلیل ہو جاتا ہے۔ لیبارٹری تجربات میں یہ تقریباً ایک گھنٹے میں تحلیل ہو گیا۔ یہ نیا پلاسٹک سیلولوز پر مبنی ہے، جو قدرتی طور پر درختوں میں موجود ہے۔ اندازاً سالانہ تقریباً 100 ارب ٹن سیلولوز پیدا ہوتا ہے۔ اس میں شامل کولین کورائینڈ اسے مضبوطی اور لچک فراہم کرتا ہے۔ ٹھیک پانی میں موجود آئیز اس کے مائیکرو بی بندھنوں کو توڑ دیتے ہیں، جس سے یہ محفوظ اجزاء میں تبدیل ہو جاتا ہے اور مائیکرو پلاسٹکس باقی نہیں رہتے۔ یہ ٹیکنالوجی درج ذیل شعبوں میں انقلاب لاسکتی ہے: خوراک کی جیکنگ، ماہی گیری کے جال، سنگل یوز اشیاء زرعی فلم۔ اگرچہ یہ ایجاد امید افزا ہے، مگر بڑے پیمانے پر پیلیجر باقی ہیں۔ مائیکرو پلاسٹکس کا بحران عالمی سطح پر ایک سنجیدہ حقیقت ہے۔ جاپانی سائنس دانوں کی یہ نئی ایجاد اس مسئلے کے حل کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ اگر اسے صنعتی سطح پر کامیابی سے نافذ کیا گیا تو یہ پلاسٹک آلودگی کے خلاف عالمی جدوجہد میں سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ پائیدار مستقبل کی جانب جوش رفت صرف سائنسی ایجادات سے نہیں بلکہ اجتماعی شعور، ذمہ دارانہ استعمال اور موثر پالیسی سازی سے ممکن ہے۔ یہ نیا پلاسٹک امیدی کی ایک کرن ہے۔ مگر اصل کامیابی اس وقت ہوگی جب انسان اپنی عادات اور ترجیحات میں بھی تبدیلی لائے گا۔

भारत की विकास यात्रा में एक नया आरंभ

‘सेवा तीर्थ’ में प्रथम कैबिनेट बैठक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में, नए प्रधानमंत्री कार्यालय ‘सेवा तीर्थ’ में केंद्रीय मंत्रिमंडल की ऐतिहासिक प्रथम बैठक आयोजित हो रही है।

यह बैठक एवं यह भवन नए भारत के नवनिर्माण की एक प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। इस शुभारंभ के साथ ही हम उस भविष्य का स्वागत कर रहे हैं, जिसके निर्माण में सदियों का श्रम लगा है। आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक में इतने दशकों तक सरकारों ने विरासत को संभाला और भविष्य के सपने देखे। हमने एक ऐसे भारत के सपने देखे, जिसकी सोच स्वदेशी हो, स्वरूप आधुनिक हो, और सामर्थ्य अनंत हो। आज ये सेवातीर्थ उसी संकल्पना का वह मूर्तिमान अवतार है जो लोकतन्त्र की जननी के रूप में भारत के गौरव को बढ़ाएगा।

आज इस अवसर पर इस स्थान के इतिहास को भी स्मरण कर रहे हैं। ‘सेवा तीर्थ’ उन अस्थायी बैरकों के स्थान पर बना है, जो ब्रिटिश काल के थे। उस स्थान पर राष्ट्र संचालन के सक्रिय संस्थान का निर्माण नए भारत के कायाकल्प का भी प्रतीक है।

गुलामी के कालखंड से पहले भारत की पहचान एक ऐसे राष्ट्र के रूप में होती थी जो एक ओर अपनी भौतिक



भव्यता के लिए भी जाना जाता था, और दूसरी ओर अपने मानवीय मूल्यों के लिए। सेवातीर्थ की संकल्पना इन दोनों ही आदर्शों से मिलकर बनी है। कर्तव्य, सेवा और समर्पण की त्रिवेणी से यह कार्यस्थल एक तीर्थ की भांति पवित्र हो, यह इसकी मूलभावना है।

‘सेवा तीर्थ’ में हो रही इस पहली बैठक के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल यह संकल्प दोहराता है कि यहां लिया गया हर निर्णय 140 करोड़ देशवासियों के प्रति सेवा-भाव से प्रेरित होगा और राष्ट्र-निर्माण के व्यापक लक्ष्य से जुड़ा होगा। हमारे लिए संवैधानिक मूल्य उस नैतिक प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति

हैं, जो शासन को नागरिक की गरिमा, समानता और न्याय से जोड़ती है। ‘सेवा तीर्थ’ की कार्य-संस्कृति इसी आत्मा से संचालित होगी, जहां हर नीति संविधान की मूल भावना के अनुरूप होगी और हर निर्णय देशवासियों की आकांक्षाओं के प्रति उत्तरदायी होगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल यह संकल्प दोहराता है कि इस परिसर में लिया गया प्रत्येक निर्णय ‘नागरिक देवो भव’ की भावना से प्रेरित होगा। यह स्थान सत्ता के प्रदर्शन का नहीं, वरन् प्रत्येक भारतवासी के सशक्तिकरण का केंद्र बनेगा। सेवा तीर्थ से संचालित शासन का हर प्रयास देश के अंतिम व्यक्ति के

जीवन को सरल बनाने की भावना से जुड़ा रहेगा। हम ये दोहराते हैं कि, हम अपने विज्ञान के मुताबिक उस गवर्नेंस मॉडल को और मजबूती देंगे, जो पारदर्शी, उत्तरदायी और नागरिक की संवेदनाओं के प्रति सजग हो।

‘सेवा तीर्थ’ उस गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता का उत्तर है, जो जड़ता की जगह गतिशीलता को, उदासीनता की जगह निष्ठा को और संदेह की जगह समाधान को बढ़ावा देता है।

इसी सोच के साथ, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते वर्षों में लिए गए निर्णयों ने शासन के उद्देश्य को नई स्पष्टता दी है। करोड़ों

नागरिकों के जीवन में आए बदलाव ने शासन के प्रति जनता के विश्वास को मजबूत किया है।

बीते एक दशक में 25 करोड़ से अधिक नागरिकों को गरीबी से बाहर निकालकर देश ने असंभव समझे जाने वाले काम को संभव करके दिखाया है। ऐसे अनेक कीर्तिमानों के पीछे सरकार की दूरगामी सोच, व्यापक विज्ञान और अथक परिश्रम रहा है। आयुष्मान भारत के माध्यम से करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा से जोड़ने का गौरव देश ने हासिल किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करीब 80 करोड़ नागरिकों तक खाद्य सुरक्षा पहुंचाकर भुखमरी के अभिशाप का अंत किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12 करोड़ से अधिक शौचालयों के निर्माण से करोड़ों परिवारों और महिलाओं को गरिमापूर्ण जीवन मिला है। ये सभी आंकड़े शासन की उस दिशा का संकेत हैं जहां नीति का अंतिम उद्देश्य नागरिक का जीवन सरल बनाना रहा है।

इसी तरह 4 करोड़ से अधिक घरों के निर्माण से करोड़ों परिवारों को सिर पर छत और सुरक्षा मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के माध्यम से षष्ठ करोड़ से अधिक नए घरों तक पीने के पानी की पहुंच सुनिश्चित हुई है।

मंत्रिमंडल ने ‘केरल’ राज्य के नाम को बदलकर केरलम करने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज ‘केरल’ राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद, राष्ट्रपति द्वारा केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को केरल राज्य विधानसभा को संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधान के तहत विचार-विमर्श हेतु भेजा जाएगा। केरल राज्य विधानसभा की राय प्राप्त होने के बाद, भारत सरकार आगे की कार्यवाही करेगी और संसद में केरल राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने हेतु केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को लागू करने के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा प्राप्त की जाएगी।

केरल विधानसभा ने 24.06.2024 को एक प्रस्ताव पारित कर राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने का निर्णय लिया, जो इस प्रकार है:

‘मलयालम भाषा में हमारे राज्य का नाम ‘केरलम’ है। 1 नवंबर, 1956 को भाषा के आधार पर राज्यों का



गठन हुआ था। केरल पिरवी दिवस भी 1 नवंबर को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही मलयालम भाषी लोगों के लिए संयुक्त केरल के गठन की प्रबल मांग रही है। लेकिन संविधान की पहली अनुसूची में हमारे राज्य का नाम ‘केरल’ ही दर्ज है। यह विधानसभा सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से संविधान के अनुच्छेद 3 के

अनुसार तत्काल कदम उठाकर राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने की अपील करती है।

इसके बाद, केरल सरकार ने भारत सरकार से संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार ‘केरल’ राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के लिए संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करने हेतु आवश्यक कदम

उठाने का अनुरोध किया है।

संविधान के अनुच्छेद 3 में मौजूदा राज्यों के नाम परिवर्तन का प्रावधान है। अनुच्छेद 3 के अनुसार, संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। अनुच्छेद 3 में आगे प्रावधान है कि इस उद्देश्य से कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना प्रस्तुत

नहीं किया जाएगा, और यदि विधेयक में निहित प्रस्ताव किसी राज्य के क्षेत्रफल, सीमाओं या नाम को प्रभावित करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट अवधि के भीतर या राष्ट्रपति द्वारा अनुमत अतिरिक्त अवधि के भीतर उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए संदर्भित किया जाना चाहिए और इस प्रकार निर्दिष्ट या अनुमत अवधि समाप्त हो जानी चाहिए।

भारत सरकार के गृह मंत्रालय में केरल राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के विषय पर विचार किया गया और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की स्वीकृति से, केरल राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष मसौदा ज्ञापन को विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि मामलों और विधायी विभाग को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया। विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि और विधायी विभाग ने केरल राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की है।

اے آئی ایمپیکٹ سمٹ 2026 ٹیکنالوجی کی نئی دنیا کی جانب اہم قدم

بچوں کے لیے محفوظ، جامع اور بااختیار مصنوعی ذہانت کے فریم ورک پر زور



تبدیلی اکثر معاشرے کی اس صلاحیت سے کہیں زیادہ تیز ہے جس کے ذریعے وہ اس کے طویل المدتی اثرات کا مکمل ادراک کر سکے۔ ان کے بقول ”بچوں کو مرکز میں رکھنے والا اے آئی کوئی اختیاری شے نہیں بلکہ حکومتوں، صنعتوں اور ان تمام اداروں کی مشترکہ ذمہ داری ہے جو ان نظاموں کی تشکیل اور نفاذ میں شریک ہیں۔“ اجلاس کا آغاز یونیٹس انڈیا کی پوتھ ایڈووکیٹ پرسدھی سنگھ کی جانب سے بچوں اور نوجوانوں کے اعلاسیے کی پیشکش سے ہوا، جو جزیئریشن آن لیمیٹڈ کی قیادت میں کیے گئے عالمی پورٹ سروے کے نتائج پر مبنی تھا۔ اس سروے میں 184 ممالک کے 54 ہزار بچوں اور نوجوانوں کے تاثرات شامل تھے، جبکہ بھارت میں بچوں کے ساتھ خصوصی مکالمے بھی کیے گئے۔ شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ اے آئی کے ڈیزائن، نفاذ اور حکمرانی کے ہر مرحلے میں بچوں کو مرکزیت دی جائے اور ان کے حقوق کو بعد از خیال کے بجائے بنیادی اصول کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ انہوں نے دنیا بھر کی حکومتوں پر زور دیا کہ وہ سرکاری و نجی شعبوں میں اے آئی نظاموں کی نگرانی کے لیے بین الاقوامی جاتی نگرانی اداروں کو نامزد یا مضبوط کریں، جن میں ٹیکنالوجی، قانون، بچوں کے حقوق، تعلیم اور ڈیٹا تحفظ کے ماہرین شامل ہوں۔ پینل مباحثے میں مختلف ماہرین اور نمائندوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اس امر پر اتفاق کیا کہ مصنوعی ذہانت کا مستقبل اسی وقت روشن ہو سکتا ہے جب اسے انسانی اقدار، بچوں کے حقوق اور سماجی ذمہ داری کے مضبوط اصولوں کے تحت آگے بڑھایا جائے۔

نے کہا کہ اے آئی کو خوف کی ٹینک سے دیکھنے کے بجائے اس کی انقلابی صلاحیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو بچوں کے مستقبل کو نئی جہت دے سکتی ہے۔ ہمیں ایسا نظام حکمرانی درکار ہے جو ہمارے بچوں اور ملک کو مکمل طور پر محفوظ رکھے، اور ساتھ ہی اس امر کو یقینی بنائے کہ بچے اے آئی کے فوائد سے بھرپور انداز میں مستفید ہو سکیں اور اپنی زندگیوں میں ہمارے مشترکہ عالمی مستقبل کی تشکیل میں فعال کردار ادا کریں۔ ہندوستان، سری لنکا، بھوٹان اور مالدیپ میں ناروے کی سفیر سے ایلین اسٹینر نے کہا کہ بچوں اور نوجوانوں کے لیے محفوظ اور جامع اے آئی ان کے ملک کی ترجیحات میں شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ناروے ٹیکنالوجی، بشمول اے آئی، کے ایسے استعمال کی حمایت کرتا ہے جو بچوں کے حقوق کو مستحکم کرے نہ کہ انہیں کمزور بنائے۔ انہوں نے ڈیجیٹلائزیشن سے وابستہ مواقع اور خطرات دونوں سے سنجیدگی سے نمٹنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ فلی کی ڈائریکٹر جنرل جیوٹی وج نے کہا کہ اے آئی تعلیم، صحت، حکمرانی اور روزمرہ کی ڈیجیٹل سرگرمیوں میں گہرائی تک سرایت کر چکا ہے اور ہندوستان سمیت دنیا بھر میں لاکھوں بچوں کے تجربات اور امکانات کو متاثر کر رہا ہے۔ انہوں نے نشان دہی کی کہ ہندوستانی ایڈجیکٹ صنعت تیزی سے اے آئی کی مطابقتی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر طلبہ کی کارکردگی کا تجزیہ کر رہی ہے اور ان کے لیے شخصی نوعیت کے تعلیمی تجربات فراہم کر رہی ہے۔ یونیٹس آف نوویشن کے گلوبل ڈائریکٹر تھاس ڈیون نے کہا کہ اے آئی اس دنیا کو نئی شکل دے رہا ہے جس میں بچے پرورش پارے ہیں، اور یہ

رہے تھے، جس کا اہتمام فلی (FICCI) نے یونیٹس کے اشتراک سے کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اے آئی نظام اب تیزی سے بچوں کے سیکھنے کے انداز، معلومات تک رسائی اور ان کے طرز عمل کی تشکیل پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ پروفیسر سوڈ نے کہا کہ ”ہم ابھی تک یہ نہیں جانتے کہ الگورتھم کی بنیاد پر چلنے والی فیڈز اور شخصی نوعیت کے تعلیمی اسپس اے آئی ساتھیوں کے ساتھ پروان چڑھنے کے طویل المدتی اثرات کیا ہوں گے۔ وقت کے ساتھ بچے کی مجموعی ذہنی، نفسیاتی اور سماجی نشوونما پر ان اثرات کو سمجھنے کے لیے مزید تحقیق اور نئے آلات کی ضرورت ہے۔“ انہوں نے اے آئی کو ”دودھاری تلوار“ قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکمرانی کے اقدامات کا محور یہ ہونا چاہیے کہ مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے اور ممکنہ خطرات کو تاحتمی الامکان کم کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ اے آئی رسائی کو بہتر بنا کر شمولیت کے فروغ میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن اس پر حد سے زیادہ اٹھار بچوں کی تنقیدی فکر اور آزادانہ مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت کو متاثر بھی کر سکتا ہے۔ حکومتی اقدامات کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ بھارت نے ’انڈیا اے آئی مشن‘ شروع کیا ہے، اے آئی گورننس فریم ورک پر کام کا آغاز کر دیا ہے، اور حال ہی میں ایک تکنیکی و قانونی خاکے کے ذریعے اے آئی کے تحفظ کو مستحکم بنانے کے لیے وائٹ پیپر جاری کیا ہے۔ وزارت الیکٹرونکس و اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے سکرٹری ایس کرشن نے کہا کہ اس سمٹ کا انعقاد آئندہ نسل کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے اور اس کا مرکزی موضوع لوگ، کردار اور ترقی ہے۔ انہوں

نے سمٹ میں اے آئی ایپلی کیشنز کو بھی دکھایا گیا ہے، جس سے اسکیل اپتیل اور موثر سسٹم کی تعمیر میں اے آئی کے کردار کو تقویت ملی ہے۔ شائقین عملی ڈیٹا سٹمٹ ماڈلز، ڈیٹا سیکورٹی کے معیارات، تعبیل کے طریقہ کار اور حقیقی دنیا کے اثرات کو سمجھنے کے لیے نمائش کنندگان کے ساتھ فعال طور پر بات چیت کر رہے ہیں۔ طلباء اور نوجوان پیشہ ور افراد کا پر جوش ردعمل کیڑے کے طور پر اے آئی میں بڑھتی دلچسپی کی عکاسی کرتا ہے۔ انڈیا اے آئی ایمپیکٹ سمٹ 2026 ایکسیو تعلیمی اداروں، صنعت اور حکومت کے درمیان تعاون کا ایک پلیٹ فارم ہے۔ نمائشوں میں زبردست آمد جدید ٹیکنالوجی تک رسائی کو جمہوری بناتے ہوئے سائنس، اختراع اور پائیداری کو مضبوط بنانے میں مصنوعی ذہانت سے چلنے والے حل کی مطابقت کو اجاگر کرتی ہے۔ سمٹ پائیدار ترقی کے لیے محفوظ، جامع اور مستقبل کے لیے تیار اے آئی ماحولیاتی نظام کی تعمیر کے لیے ہندوستان کے عزم کو اجاگر کرتی ہے۔ حکومت ہند کے پرنسپل سائنسی مشیر پروفیسر اے کمار سوڈ نے اس امر پر زور دیا کہ بچوں کے لیے ایسا مصنوعی ذہانت (اے آئی) فریم ورک تشکیل دیا جائے جو محفوظ، جامع اور انہیں بااختیار بنانے والا ہو۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی تیز رفتار رسائی کے باعث بچوں کا اے آئی سے چلنے والے پلیٹ فارمز سے واسطہ غیر معمولی طور پر بڑھ گیا ہے۔ وہ یہاں اے آئی ایمپیکٹ سمٹ 2026 کے موقع پر اے آئی اور بچے کے اے آئی کے اصولوں کو محفوظ، جامع اور بااختیار بنانے کے لیے عملی جامہ پہنانا، کے عنوان پر منعقدہ اجلاس سے خطاب کر

نئی دہلی: انڈیا اے آئی ایمپیکٹ سمٹ 2026 کے تیسرے دن، 10 پولینوں میں پھیلی ہوئی ایکسیو ایک بڑی کشش کی چیز بنی ہوئی ہے، جس میں صنعت کے قائدین، اشارت ایس، تعلیمی اداروں، سرکاری نمائندوں اور شہریوں کی مضبوط شرکت ہے۔ جدید ترین مصنوعی ذہانت (اے آئی) ٹولز اور ٹیکنالوجیز کے براہ راست مظاہرے دیکھنے کے لیے خراب موسم کے باوجود نمائش کے میدان میں نوجوانوں اور طلباء کی ایک بڑی تعداد دیکھی گئی۔ ایکسیو کا ایک اہم نوٹس ایریا اے آئی پر مبنی سائبر سیکورٹی، فنڈیک حل ہے جو ابھرتے ہوئے خطرات کے خلاف ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو مضبوط کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ نمائش کنندگان نے ڈیجیٹل کامرس کے اگلے مرحلے کے لیے ایڈوانسڈ میجیٹ ڈیجیٹل انڈر سٹریٹس (ایم ڈی آر) پلیٹ فارمز، اے آئی سے چلنے والے تھریٹ انٹیلی جنس سسٹم، ملٹی لیز ڈیٹا پوینٹیشن۔ فرسٹ سیکورٹی فریم ورک، محفوظ اینڈ ٹو اینڈ اے آئی لین دین کی نمائش کی ہے۔ یہ حل بے ضابطگیوں کا پتہ لگانے، سائبر حملوں کو روکنے اور واقعات کا تیزی سے جواب دینے کے لیے مصنوعی ذہانت کو انسانی مہارت کے ساتھ جوڑتے ہیں، اس طرح خطرات کو کم کرتے ہیں اور اہم ڈیجیٹل اثاثوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق، پیش گوئی کے تجزیات، حقیقی وقت کی نگرانی، اور اے آئی سے چلنے والے رسپانس سسٹم کاروبار، سرکاری محکموں، اور سرکاری اداروں کو سائبر سیکورٹی کے نظام کو مضبوط کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ نمائش میں گورننس، انٹر پرائز سٹریٹجی انٹیگریشن، اسٹارٹ اپ ربن پلیٹ فارمز اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر

दिल्ली: अदालत ने भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

दिल्ली की एक अदालत ने भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

अधिकारियों के अनुसार चिब पर विरोध प्रदर्शन का मुख्य षडयंत्रकारी होने का आरोप है। बताया जा रहा है कि वह राष्ट्र विरोधी नारा लगाने में शामिल था। चिब के साथ श्री कृष्णा हरि, कुंदन यादव, नरसिम्हा



यादव और अजय कुमार यादव भी सह आरोपी हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि चिब ने पूछताछ के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों पर

हमला किया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच चल रही है और आगे की पूछताछ तथा उचित जांच के लिए चिब की हिरासत की अवधि बढ़ाए जाने

की मांग की गई है।

चिब को भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत हिरासत में लिया गया है। इनमें विभिन्न समूहों के बीच धर्म, जाति, जन्मस्थान, आवास और भाषा के आधार पर नफरत फैलाने से निपटने के लिए लगाई जाने वाली धारा 196 भी शामिल है। यह अपराध गैर जमानती है। समिट के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की चल रही जांच का मामला दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सौंप दिया गया है।

सिक्किम के सोरेंग जिले के दो वार्डों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए

सिक्किम के सोरेंग जिले के दो वार्डों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। जिला प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों और संभावित संक्रमित क्षेत्रों को सतर्क कर दिया है। स्वास्थ्य और पशुपालन टीमों को प्रभावित क्षेत्र में स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजा



गया है। जिला प्रशासन स्थिति पर नजर रख रहा है।

जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में सामान्य से अधिक दर्ज किया गया तापमान

जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 10 से 11 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने इस महीने के अंत तक राज्य में शुष्क मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। श्रीनगर में

अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस वर्ष के सामान्य तापमान से 6 डिग्री अधिक है। गुलमर्ग के स्की रिसॉर्ट में अधिकतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से - डिग्री अधिक है।

MSP परचना मसूर व सरसों खरीद को चार राज्यों को मंजूरी

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने 12 सफदरजंग रोड स्थित आवास पर 11 राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से विस्तृत समीक्षा बैठक की। इस दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) एवं कृषि उन्नति योजना (KY) के अंतर्गत राज्यों में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा इन दोनों योजनाओं में जारी धनराशि के प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध उपयोग पर विशेष बल देते हुए कहा कि योजनाओं का उद्देश्य केवल बजटीय व्यय करना नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर किसानों की आय में ठोस वृद्धि सुनिश्चित करना है।

चौहान ने राज्यों से आग्रह किया कि उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोग 31 मार्च 2026 तक पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसानों को योजनाओं का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि समयबद्ध व्यय के साथ-साथ गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही भी उतनी ही



आवश्यक है।

बैठक में कृषि अवसंरचना सुदृढ़ीकरण, तकनीकी नवाचार, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन, बीज वितरण, फसल विविधीकरण तथा मूल्य संवर्धन जैसी पहलों पर भी चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने राज्यों से कहा कि वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं का क्रियान्वयन करें तथा नवाचार आधारित परियोजनाओं को प्राथमिकता दें, जिससे किसानों की लागत घटे और उत्पादकता में वृद्धि हो। बैठक के दौरान रबी विपणन सत्र के अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा फसलों की खरीद के संबंध में प्रस्तुत प्रस्तावों पर भी विचार-विमर्श किया गया। किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए निम्नलिखित स्वीकृतियाँ प्रदान की गईं जिसमें मध्य प्रदेश को चना एवं

मसूर की खरीद की स्वीकृति, राजस्थान एवं गुजरात को चना एवं सरसों की खरीद की स्वीकृति, महाराष्ट्र को चना की खरीद की स्वीकृति शामिल हैं।

इन स्वीकृतियों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अनुरूप प्राप्त हो सके तथा बाजार में मूल्य स्थिरता बनी रहे।

केंद्रीय मंत्री ने राज्यों को निर्देश दिया कि खरीद प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण की जाए, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि खरीद केंद्र पर्याप्त मात्रा में हों, तौल, भंडारण एवं भुगतान की प्रक्रिया पारदर्शिता एवं ईमानदारी से संचालित हो तथा किसानों को न्यूनतम आवश्यक

सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

चौहान ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से ही कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है। उन्होंने राज्यों से अपेक्षा की कि वे योजनाओं के क्रियान्वयन में नवाचार, तकनीक और पारदर्शिता को प्राथमिकता दें, जिससे किसानों का विश्वास और सुदृढ़ हो।

बैठक के अंत में राज्यों के प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया कि वे योजनाओं के अंतर्गत धनराशि के समयबद्ध एवं प्रभावी उपयोग के लिए तेजी से कार्य करेंगे तथा किसानों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे।

बैठक में गुजरात के कृषि मंत्री जीतूभाई, असम के अतुल बोरा, बिहार के रामकृपाल यादव, महाराष्ट्र के दत्तात्रेय भरणे, उत्तराखंड के गणेश जोशी, राजस्थान के किरोड़ी लाल मीणा, हरियाणा के श्याम सिंह राणा, केरल के पी. प्रसाद तथा मध्य प्रदेश के ऐदल सिंह, कृषि मंत्रालय के सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्य समाचार अगरतला से कोलकाता के लिए यात्री बस सेवा आज से शुरू



अगरतला से ढाका होते हुए कोलकाता के लिए यात्री बस सेवा लंबे अंतराल के बाद आज फिर से शुरू हो गई। त्रिपुरा के परिवहन और पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी तथा त्रिपुरा सड़क परिवहन निगम के अध्यक्ष समर राय यात्रियों का औपचारिक स्वागत करने के लिए इस अवसर पर उपस्थित थे।

परिवहन मंत्री श्री चौधरी ने इस सेवा के पुनः शुरू

होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार और पर्यटन सहित समग्र संबंधों में बांग्लादेश की नव निर्वाचित सरकार की भूमिका पर आशा व्यक्त की।

अधिकारियों ने कहा कि बहुप्रतीक्षित अगरतला-ढाका-कोलकाता अंतरराष्ट्रीय बस सेवा के पुनः शुरू होने से सीमा पार व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुंडका विधानसभा में 200 करोड़ रुपए का किया शिलान्यास

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मुंडका विधानसभा क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि वर्षों से उपेक्षित पड़े दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड को एक हजार करोड़ का बजट प्रदान किया गया है जिससे गांवों का विकास लगातार आगे बढ़ सके। उन्होंने बताया कि पिछले एक साल में



एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का राज्य स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया



एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत विजयवाड़ा के लोक भवन में आयोजित अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य स्थापना दिवस समारोह में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस. अब्दुल नजीर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने दोनों राज्यों की समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की सराहना की। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को भोर की रोशनी से जगमगाते पहाड़ों की भूमि बताया। यह अपनी धुंध भरी चोटियों, मठों, झीलों और जीवंत परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। मिजोरम के संदर्भ में उन्होंने इसके 84 दशमलव पांच प्रतिशत वन क्षेत्र और विविध जनजातीय आबादी का उल्लेख किया और बांस के डंडों के साथ लयबद्ध समन्वय में किए जाने वाले लोकप्रिय मिजो चराव या बांस नृत्य का भी जिक्र किया।

دین و دنیا کی ہم آہنگ تعلیم وقت کی اہم ضرورت: نئی دہلی میں جلسہ بعظمت قرآن منعقد، 14 حفاظ کی دستار بندی

نئی دہلی (ٹاپ نیوز) قرآن کریم سراسر نور ہدایت اور دنیا و آخرت کی فلاح کا ضامن ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ نئی نسل کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم سے بھی آراستہ کیا جائے، تاکہ وہ دینی اقدار کی پاسداری کے ساتھ عصری تقاضوں کو پورا کر سکے اور معاشرے کی قیادت کا فریضہ انجام دے۔ ان خیالات کا اظہار جامعہ اسلامیہ اشاعت الاسلام، ہستی حضرت نظام الدین، کلاں مسجد، نئی دہلی کے زیر اہتمام منعقدہ جلسہ بعظمت قرآن میں علمائے کرام نے کیا۔ اجلاس کی صدارت مدرسہ کے مہتمم مولانا محمد احمد رحیمی نے فرمائی جبکہ نظامت کے فرائض مفتی عبدالواحد قاسمی نے انجام دیے۔ اس بابرکت موقع پر ملک کی ممتاز دینی شخصیت چیف امام ڈاکٹر عمیر احمد ایبائی بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ ان کے ہمراہ دیگر اکابر علمائے کرام اور ائمہ عظام کے دست مبارک سے 14 حفاظ کرام کی دستار بندی عمل میں آئی۔ تقریب کا ایک نہایت ایمان افروز اور قابل ذکر پہلو یہ رہا کہ ایک طالب علم محمد یاسر نے محض ۲۶ دن میں قرآن کریم حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی، جو کلام الہی کے اعجاز کی روشن مثال ہے۔ اس موقع پر مہتمم مدرسہ مولانا محمد احمد رحیمی نے سالانہ تعلیمی رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کریم کی خدمت اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے، اور اسی کی برکت سے یہ اجتماع ممکن ہوا۔ انہوں نے زور دیا کہ مسلمانوں کی فلاح قرآن وحدیث کی عملی پیروی میں مضمر ہے۔ دین کی خدمت صرف علما کی ذمہ داری



تاریخ و اخلاقی اقدار رہنمائی کریں۔ انہوں نے مولانا محمد احمد رحیمی کی قوم کے نونہالوں کے لیے قائم کردہ تعلیمی نظام کو لائق تحسین قرار دیا۔ خصوصی شرکت کرنے والے اساتذہ مفتی ابرار احمد اور مولانا عارف ندوی نے کہا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا محفوظ کلام ہے اور اس کے تحفظ کی ذمہ داری خورد پ کائنات نے لی

نہیں، بلکہ ہر مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق اس کا مکلف ہے؛ علما، اخلاص، حکمت اور نری سے رہنمائی کریں اور عوام تعاون و اعتماد کے ساتھ ان کا ساتھ دیں۔ مہمان خصوصی ڈاکٹر عمیر احمد ایبائی نے دینی تعلیم کے ساتھ عصری علوم کے امتزاج پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ دین کی تعلیم آخرت سنوارتی ہے اور

نئی دہلی: قومی راہدہانی میں ایک طرف اسے آئی ایم ایٹ سٹ ہندوستان کو مصنوعی ذہانت کی عالمی طاقت کے طور پر قائم کرنے کی دوسری طرف ملک کی اقتصادی راہدہانی مہاراشٹر سے آئی کے علاقہ استعلا کی چونکا دینے والی خبر نے ٹیکنالوجی کے تاریک پہلو کو بے نقاب کر دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 18 فروری کو گز چروٹی خلیج کے چاموشی میں بے ہوش وار جو بیڑ سائنس اینڈ آرٹس کالج واقع امتحانی مرکز میں 12 ویں جماعت کے پویشکل سائنس پیپر میں اجتماعی نقل کی بڑی سازش کا پردہ فاش کیا گیا۔ سوال نامے کی تصویر باہر بھیج کر چیٹ جی پی ٹی سے جواب نکال کر ان کی پرنٹ کاپی مرکز تک پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ اس سسٹی میز معاملے میں 13 اساتذہ اور ایک چھاپی کو معطل کر دیا گیا ہے اور پولیس مقدمہ

چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے 12 ویں کے امتحان میں اجتماعی نقل کی سازش، 3 اساتذہ سمیت 4 معطل



نئی دہلی: قومی راہدہانی میں ایک طرف اسے آئی ایم ایٹ سٹ ہندوستان کو مصنوعی ذہانت کی عالمی طاقت کے طور پر قائم کرنے کی دوسری طرف ملک کی اقتصادی راہدہانی مہاراشٹر سے آئی کے علاقہ استعلا کی چونکا دینے والی خبر نے ٹیکنالوجی کے تاریک پہلو کو بے نقاب کر دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 18 فروری کو گز چروٹی خلیج کے چاموشی میں بے ہوش وار جو بیڑ سائنس اینڈ آرٹس کالج واقع امتحانی مرکز میں 12 ویں جماعت کے پویشکل سائنس پیپر میں اجتماعی نقل کی بڑی سازش کا پردہ فاش کیا گیا۔ سوال نامے کی تصویر باہر بھیج کر چیٹ جی پی ٹی سے جواب نکال کر ان کی پرنٹ کاپی مرکز تک پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ اس سسٹی میز معاملے میں 13 اساتذہ اور ایک چھاپی کو معطل کر دیا گیا ہے اور پولیس مقدمہ

نئی دہلی: قومی راہدہانی میں ایک طرف اسے آئی ایم ایٹ سٹ ہندوستان کو مصنوعی ذہانت کی عالمی طاقت کے طور پر قائم کرنے کی دوسری طرف ملک کی اقتصادی راہدہانی مہاراشٹر سے آئی کے علاقہ استعلا کی چونکا دینے والی خبر نے ٹیکنالوجی کے تاریک پہلو کو بے نقاب کر دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 18 فروری کو گز چروٹی خلیج کے چاموشی میں بے ہوش وار جو بیڑ سائنس اینڈ آرٹس کالج واقع امتحانی مرکز میں 12 ویں جماعت کے پویشکل سائنس پیپر میں اجتماعی نقل کی بڑی سازش کا پردہ فاش کیا گیا۔ سوال نامے کی تصویر باہر بھیج کر چیٹ جی پی ٹی سے جواب نکال کر ان کی پرنٹ کاپی مرکز تک پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ اس سسٹی میز معاملے میں 13 اساتذہ اور ایک چھاپی کو معطل کر دیا گیا ہے اور پولیس مقدمہ

یوپی کے 6 ایئر پورٹس سے پروازیں بند، کھلیش یادو کا طنز

سرخ پے "اتر پردیش: 5 سال میں 7 ایئر پورٹ کھلے اور اب 6 پر پروازیں بند ہیں۔" اس کے کپشن میں سابق وزیر اعلیٰ نے لکھا کہ "ہوا ہوائی ہو گئے ہوائی اڈے! دراصل بی جے پی حکومت میں کوئی بھی منصوبہ یا تعمیراتی کام صرف سرکاری خزانے سے پیسے نکالنے کا ذریعہ ہوتا ہے، تاکہ بدعنوانی پر پردہ ڈالا جاسکے۔ اسی لیے بی جے پی کی بنائی ہوئی پانی کی تنکیاں گر رہی ہیں یا ان سے مسلسل دھاریں پھوٹ رہی ہیں۔" کھلیش یادو نے مزید لکھا کہ "مندر سے لے کر پارلیمنٹ تک کی چھتیں ٹپک رہی ہیں۔ سڑکیں بدحال ہیں اور بی جے پی کے بنائے ہوئے ایکسپریس دے لاگت اور کیشن خوری کے نئے ریکارڈ قائم کر رہے ہیں۔"



لکھنؤ: سماج وادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ کھلیش یادو نے مرکز اور یوپی کی بی جے پی حکومتوں کو تعمیراتی کاموں اور ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ بی جے پی کے دور حکومت میں کئی سرکاری منصوبے اور تعمیراتی کام معیار کی کمی اور بدعنوانی کی زد میں ہیں۔ کھلیش یادو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'اٹکس' پر 'آج تک' کی خبر کا ایک اسکرین شاٹ پوسٹ کیا جس کی

ایس آئی آر کے بعد 9 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کم ہو گئے 70.1 کروڑ ووٹر

نئی دہلی: ہندوستان کی 6 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام کچھ علاقوں میں ووٹرز کی خصوصی نظر ثانی (ایس آئی آر) کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اس دوران الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اس عمل میں بڑی تعداد میں ایسے ووٹرز کے نام حذف کئے گئے ہیں جو نااہل پائے گئے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 9 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ووٹرز کی تعداد مجموعی طور پر 1 کروڑ 70 لاکھ سے زیادہ کم ہوئی ہے۔ کمیشن نے واضح کیا ہے کہ حذف شدہ ووٹرز اور نئے شامل کیے گئے اہل ووٹرز کے درمیان فرق کی بنیاد پر یہ خالص تبدیلی ہے۔ چیف الیکٹورل آفیسر کے اعداد و شمار کے مطابق گجرات، پڑچیری، لکھنپ، راجستھان، چھتیس گڑھ، انڈمان اور گوبار جازر، گوا اور کیرالہ سمیت 9 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ایس آئی آر شروع ہونے سے پہلے تقریباً 45.21 کروڑ تھی۔ حتیٰ ووٹرز جاری ہونے کے بعد یہ تقریباً 75.19 کروڑ رہ گئی، یعنی 70.1 کروڑ سے زیادہ ووٹ کم ہوئے۔ سب سے زیادہ نام گجرات میں حذف کئے گئے ہیں۔ یہاں 68 لاکھ 12 ہزار 711 ووٹرز کو



فیصلہ کی درج ہوئی ہے۔ اس کے بعد مدھیہ پردیش آتا ہے جہاں تقریباً 25.34 لاکھ نام ہٹائے گئے اور ووٹرز کی تعداد 74.5 کروڑ سے کم ہو کر 40.4 کروڑ رہ گئی ہے۔ یعنی تقریباً 40.13

کروڑ سے گھٹ کر 39.5 کروڑ ہو گئی۔ دیگر ریاستوں میں بھی بڑی تعداد میں ووٹوں کے نام حذف کردیے ہیں۔ راجستھان میں تقریباً 36.31 لاکھ ووٹرز کے نام ہٹائے گئے جبکہ چھتیس گڑھ میں تقریباً 99.24 لاکھ اور کیرالہ میں تقریباً 97.8 لاکھ نام کاٹے گئے۔ چھوٹی ریاستوں جیسے گوا میں تقریباً 27.1 لاکھ ناموں کو ہٹا دیا گیا۔ مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں انڈمان اور گوبار، پڑچیری اور لکھنپ میں بھی ووٹرز کی تعداد میں کمی درج کی گئی۔ کمیشن نے بتایا کہ مغربی بنگال، اتر پردیش اور جموں ناڈو کے اعداد و شمار اس ماہ کے آخر تک جاری کیے جائیں گے۔ ملک بھر کی 12 ریاستوں میں جاری عمل کا اگلا مرحلہ اپریل میں شروع ہوگا جس کے تحت پورے ملک میں ووٹرز کی تصدیق کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس عمل کے دوران شیڈول میں کئی تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں۔ بہار کی طرح ہی تمل ناڈو اور مغربی بنگال میں سیاسی جماعتوں نے اس عمل کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ یہ مہم ووٹرز کو درست اور اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ آسام میں ایس آئی آر کی جگہ نظر ثانی کا خصوصی عمل اپنایا گیا تھا جو 10 فروری کو مکمل ہو چکا ہے۔